पुस्तकालय

226
18-7-02

असंशोधित

10 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० सं० मु० (एल० ए०) 86—मोनो—1000—16-3-2002—,

टर्न-27/मधुप/10.7.2002

§ अन्तराल के बाद §

§ इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया । §

वित्तीय-कार्य

अध्यक्ष : माननीया प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्रीमती रमा देवी §मंत्री§ : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि –

"लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 2,60,86,72,000 §दो अरब, साठ करोड़, छियासी लाख, बहत्तर हजार§ रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इन अनुदान की माँग पर कटौती-प्रस्ताव क्रमांक – 144 से 150 व्यापक हैं । जो सर्वश्री भोला प्रसाद सिंह, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, अश्विनी कुमार चौबे, प्रेम कुमार, अमरेन्द्र प्रताप सिंह, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल एवं सत्यदेव राम के हैं । मैं विचार-विमर्श हेतु उसी को लेता हूँ । माननीय सदस्य, श्री भोला प्रसाद सिंह जी, अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि –

"इस शीर्षक की माँग 10 रुपये से घटायी जाय ।"

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल इसपर बोलेंगे ।

टर्न-27/मधुप/10.7.2002

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस सदन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी द्वारा, विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है और प्रतिवेदन के अन्तिम पृष्ठ पर जो शब्द प्रींट किये गये हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसपर काफी अच्छे शब्दों में, प्लास्टिक कोटेड पेपर पर यह छपा है - "जल है जीवन-स्वच्छता प्राण"। काफी अच्छी बात है और इनका बजट लगभग 2.5 अरब रूपये का है, इनको और पैसे की आवश्यकता है, और पैसा इनको मिलना चाहिये लेकिन महोदय, एक तरफ "स्वच्छता प्राण, जल है जीवन", एक साथ ये जोड़ती हैं और दूसरी तरफ आज तक इन्होंने 11 प्रतिशत आबादी को ही स्वच्छता सुविधा प्रदान की है यानि आज भी 89 प्रतिशत आबादी स्वच्छता सुविधा से वंचित है और महोदय, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो इनके प्रतिवेदन में अंकित है, इनके एन0एस0एस0 के द्वारा कराया गया जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके माध्यम से ही इन्होंने प्रतिवेदन में अंकित किया है और यह उन्हीं के शब्दों में है, महोदय, आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। (क्रमशः)-

(इस अवसर पर श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (सभापति) ने आसन ग्रहण किया।)

टर्न:28:अमनो:दि0 10.7.02

...क्रमशः...

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति हेतु सर्वेक्षण कराये हुए दस वर्ष हो गये। यानि जब से ये सरकार चला रही हैं, जब से ये सरकार में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की कैसी सुविधा है, कैसी व्यवस्था है, हमारे ग्रामीण शुद्ध जल पी रहे हैं या अशुद्ध जल पी रहे हैं, इसके बारे में सर्वेक्षण कराने का इनको समय नहीं है। मैं यह बात अपने से नहीं कह रहा हूँ बल्कि इनके प्रतिवेदन में छपी हुई बातों को उद्धृत कर रहा हूँ। महोदय, जब यह कहती हैं कि हमें पैसा चाहिए और दूसरी तरफ जो पैसा इनको 2000-01 में दिया गया वह पैसा भी खर्च नहीं कर पातीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप पैसा मांगिए, पैसा लीजिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करें, बच्चों को शुद्ध पेय जल की आवश्यकता है खासकर विद्यालय में जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ सामाजिक न्याय की सरकार में रहनेवाले बच्चे पढ़ने जाते हैं ... उन बच्चों को शुद्ध पेय जल की आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है वहाँ पर कीजिए। लेकिन आप इसको कर नहीं रही हैं। पैसा आपको दिया जा रहा है लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज इतने महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है और आप आपस में बातें कर रही हैं, सुनने में थोड़ा दिलचस्पी रखिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह विभाग विकास का विभाग है। एक तरफ जहाँ आप योजना मद में खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा आप गैर योजना मद में खर्च कर रहे हैं। जबकि यह विकास से संबंधित विभाग है। इसमें आपको योजना मद में ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। योजना मद में आपने 1अरब22करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वहीं आप गैर योजना मद में 1अरब 38 करोड़ 71लाख 72 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं। इसपर

टर्न:28:अंमनो: दि0 10·7·02

भी आपका ध्यान बजट बनाते समय रहना चाहिए । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि विगत सत्र में माननीय मंत्री ने कुछ बोली थी और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया था कि माननीय सदस्यों के अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत कु. को और प्रत्येक वार्ड के लिए 5 - 5 चापाकल देंगे ।

···क्रमशः···

श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल : (क्रमश:) महोदय क्या हुआ इनके आश्वासन का, क्या हुआ इस सदन में वक्तव्य देने का ? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो शब्द कहे थे, उस पर अनुकरण कीजिए । अनुकरण किये बिना यह बजट लाने से, उनको पैसा देना हमें लगता है कि वह नकारा साबित होगा, जब तक हम इसको सही तरीके से लागू नहीं कर पायेंगे । जिन गरीबों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है अभी तक तो सरकार को पैसा देना नकारा साबित हो रहा है ।

सभापति महोदय, 31 मार्च, 2000 में जो लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है, लेखा परीक्षक ने इसके विभाग के बारे में जो रिपोर्ट में टिप्पणी की है, उसमें इन्होंने जो दर्शाया है, ग्रामीण जनता के लाभ हेतु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना का जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें भी पैसा जो दिया गया है, खासकर इस योजनामें भागलपुर के लिए जो पैसा दिया गया था, जो अनुबंध किये गये थे 1.18 करोड़ रू0 का, उसमें भी घोटाले हुए हैं, इस पैसे का भी सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सका है । महोदय, ये मंत्री हैं, हर जगहों पर, हरेक चीजों को सारी तो नहीं देख सकती हैं लेकिन इनका विभाग बड़ा विभाग है, विभाग में अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उसमें भी कई एक विभागों में ये विभाग बने हुए हैं, विभागीय पदाधिकारी सही तरीके से काम करें, इस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना इनका कर्त्तव्य है लेकिन इनका ध्यान कम रहता है । हमलोग इनके नाम से और इनके कार्य के बारे में काफी संतोष व्यक्त करते थे लेकिन जब कार्य को देखने का मौका मिला, जब इनके कार्य से जो अनुभव हुए हैं, वह पूरा का पूरा विभाग नकारा साबित हो रहा है । आज भी पूरे राज्य में शुद्ध पेयजल देने को यह सरकार, यह विभाग

अभी साबित हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस शब्द की ओर, इस विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। महोदय, इनका जो प्रतिवेदन है वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 का, इसमें कई विभागों की चर्चा काफी तन्मयता के साथ, काफी सुन्दर-सुन्दर चित्र लोगों को देखने लायक, शब्द काफी अच्छा छपा हुआ है। आपके विभाग का प्रतिवेदन भले प्लास्टिक कोटेड में छपा हुआ नहीं हो लेकिन लोगों को का स्वास्थ्य अच्छा हो, इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जरूर दें। आखिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपना जीवन गुजर-बसर कैसे कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। शहरों की भी यही स्थिति है। शहरों में भी पाईप लाईन की व्यवस्था काफी जर्जर स्थिति में है। महोदय, हमलोग एम०एल०ए० फ्लैट में रहते हैं, मैंने जीरो आवर में ही पानी के संबंध में चर्चा की थी। कहीं पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं पर हजारों लिटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है, पानी नाला में बह रहा है, मैंने दोबारा भी सदन का ध्यान इस ओर ले गया था। महोदय, मैं कह रहा हूँ कि .....

(क्रमशः)

न-30/ 10-7-2002/मुश्ताक

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल :- पानी जो बहना शुरू हुआ , इनका पानी बंद ही नहीं हो रहा है ,जो सड़क बनायी गयी है ,उस सड़क पर पानी लग गया है और इसके कारण वह सड़क भी बर्बाद हो रहा है । माननीय मंत्री ,नगर विकास विभाग ,जो बैठे हुए हैं,इन्होंने आश्वासन दिया था विगत 4 जुलाई को कि इसको आज ही बंद करा देंगे । मैं माननीय नगर विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह पानी आज भी बह रहा है ,गंदा नाली में पानी बह रहा है और सदन में कहा गया था कि आज ही वह बंद करा देंगे ,जरा इस पर ध्यान दीजिए ,नहीं तो इसमें आज रिक्शा ,गाड़ी की धोलाई की जा रही है ,आप उसे कम से कम एक गैरेज के रूप में दे दीजिए ,कार और गाड़ी की सफाई तो होगी लेकिन आप नहीं दे सकते हैं तो झूठ मूठ आपका जो रपट है वह एक पुलंदा है ,यह प्रतिवेदन जो प्लास्टिक कोटेड किताब दिया गया है ,सब बेकार है,नाकारा है ।

महोदय ,कोसी में अमृत पेयजल आपूर्ति योजना देने का जो प्रतिवेदन में छपा है ,कोसी में अमृत पेयजल योजना प्रभावित है ,हमलोग वहां पानी दे रहे हैं लेकिन आज भी वह बेकार है । महोदय ,मैं सारण जिला की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सारण जिला में खासकर छपरा और रिविलगंज पुराना नगरपालिका है और दोनो नगरपालिकाओं में पेयजल की जो इनकी व्यवस्था है ,वह नाकारा है ,ये लोगों को पाईप लाईन से पानी नहीं दे सकते हैं ,कभी पम्प चलता है तो पाइप बेकार हो जाता है और जब पाईप ठीक किया जाता है तो पम्प बेकार हो जाता है । इस तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । बिहार में एकमात्र अस्पताल पी0एम0सी0 एच0 में तीन पम्प लगे हुए हैं , दो पम्प कौर्टज कम्पाउंन्ड में है ,वर्षों से पम्प चल रहा था ,यह बंद हो गया तो इसे बनाया गया तो पाईप खराब हो गया ,लोग पानी बिना तरस रहे हैं । दूसरा इमरजेन्सी में पम्प लगा हुआ है ,वह पम्प भी खराब हो गया है और इसमें बालू आ रहा है ।

सभापति [श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव]:- माननीय सदस्य ,अब खत्म करें । अब माननीय सदस्य श्री जगदीश नारायण चौधरी बोलेंगे ।

श्री जगदीश नारायण चौधरी :- सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितनी उपलब्धि आज तक इस सरकार ने की है, मैं समझता हूं कि विगत वर्षों में उसका अंश भी नहीं हुआ है। इसका कारण है जैसा कि अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि और केवल 1990 की जलापूर्त्ति योजना की चर्चा कर रहे थे। जो विकास की योजनायें हैं, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। जबसे सामाजिक न्याय की सरकार बनी है, इसका ध्यान ग्रामीण जनता जो भूखी है जो जल के अभाव में तड़प रहे हैं वैसे लोगों के लिए, वे स्वयं स्वीकार करते हैं, इन्होंने अपने अंतिम शब्द में सभी उपलब्धियों को नाकारा कहने का प्रयत्न किया है, नाकारा साबित करने का प्रयास किया है। आप स्वयं देखियेगे जो योजना चल रही है और इसके पूर्व 1990 में जो सामाजिक न्याय की सरकार की स्थापना हुई, आज तक माननीय लालूजी और माननीय मुख्य मंत्री महोदया जितने लोग हैं सबों की चेष्टा यही रही है कि स्वच्छ जल मिले, शौचालय की व्यवस्था हो जाए और जो इन्होंने संख्या 1 प्रतिशत, उससे मैं भी सहमत नहीं हूं, सरकार ने शौचालय बनाने की दिशा में प्रयास की है और जो गांव में लाखों गरीब लोग बसे हुए हैं जिनके पास साधन नहीं है अपने यहां शौचालय निर्माण करने की, वैसे लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है और केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ सहायता देने की बात की है जिसके लिए 15 जिलों की एक सूची बनी है।

क्रमशः

टर्न- 31/ विजय 10.7.02

श्री जगदीश नारायण चौधरी : क्रमशः सभापति महोदय, सरकार ने भी स्वयं स्वीकार किया है और शौचालयों की संख्या इसमें ... सन्निहित है । सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि गांवों में गरीब लोगों के पास जिनको साधन नहीं है उनके लिए शौचालय का निर्माण कराकर शौचालय की व्यवस्था की जाय । इस संबंध में केन्द्र सरकार को भी लिखा गया है । 2001-2002 में जो जलापूर्ति योजना बनी उस दिशा में कारगर कदम उठाया गया है और और जितने पैसे का प्रावधान किया गया था उसमें मात्र कुछ ही पैसे बचे हैं, सारे पैसे खर्च हो गए ।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों में जाकर के देखेंगें तो पायेंगे कि पहले ही जो पाइप या नलकूप बना था उसमें 80 प्रतिशत पाइप ह नष्ट हो गया है वह ऐसी स्थिति में है कि काम नहीं कर रहा है । इस दिशा में गत वर्ष सरकार ने जो काम किया तो हमने देखा अपने क्षेत्र की बात मैं कहता हूं कि मिलाकर 94 चापाकल का निर्माण कराया गया है । जो पुराने नलकूप थे उन नलकूपों की मरम्मति करायी गयी है । सरकार ने इस बारे में लक्ष्य बनाया है कि जो नलकूप पुराने पड़े हुए हैं उनकी मरम्मति करा देने से अच्छा होगा । उसके जगह नया चापाकल का निर्माण किया जाय ... सरकार का यह दृष्टिकोण है । सरकार इसमें प्रयत्नशील है । लेकिन विपक्षी सदस्यों की दृष्टि इससे हट कर है । इस सरकार को नाकारा साबित करना ही उनका काम है लेकिन यह सफल सरकार है । सभापति महोदय, यह उनकी मानसिकता का दोष है । प्राचीन काल में भी जब राजा राजा थे वनवासी थे ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, ऋषि और अगस्त मुनी के पास जाकर उन्होंने ने कहा कि राक्षस द्वारा अत्याचार हो रहा है इससे मुक्ति दिलायें तो अगस्त मुनी ने बाण दिया, अमोघ शस्त्र दिया । इसी तरह जब सीता का हरण हुआ तो जटायु थे पक्षी थी उन्होंने ने अपना प्राण उनको बचाने के लिए त्यागा । इसी तरह सीता को खोजने के लिए ... दिया गया कि जाकर वानर से मित्रता कीजिये । मानसिकता देखी जाय कि लोग स्वयं कूदेंगे नहीं लेकिन चाहेंगे कि दूसरे के माध्यम से काम हो । यह जो ... मानसिकता है उसको दूर करना होगा । सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी जो अधिकारियों की मानसिकता बनी हुई है, ... अधिकांश अधिकारियों ... मानसिकता बनी हुई है कि प्रशासनिक

टर्न-31 / विजय 10.7.02

अधिकार जो मिला है उसका कैसे दुरुपयोग हो । कैसे दुरुपयोग करें । ... जिन लोगों में ऐसी मानसिकता बनी हुई है उनके दिल में यह भावना नहीं है कि जनहित का पक्ष कर्त्तव्य उनका है । ऐसी मानसिकता रख दी गयी है ताकि सरकार बदनाम हो और लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो । इस दिशा में सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा । ऐसे अधिकारियों को जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए । ताकि उदाहरण पेश हो सके और दूसरे अधिकारी भी सीख ले सकें । ऐसा काम नहीं करें जो सरकार के विरोध में हो । सभापति महोदय, एक और बात मैं कहना चाहता हूं नकारा शब्द कह कर सरकार को अपमानित करने का काम किया जाता है । महात्मा गांधी, श्री भीम राव अम्बेदकर, लोहिया, कर्पूरी जी और अंत में हमारे सामाजिक न्याय के श्री लालू प्रसाद जी तथा माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनका प्रयास यही होता है कि गरीबों की भलाई हो । उन गरीबों के प्रति उनके दिल में दर्द है, वे उसी समाज से आए हैं, भुक्तभोगी हैं इसलिए उनके दिल में गरीबों का ख्याल उनके दिल में रहता है कि कैसे समाज में जो शोषित पीड़ित गरीब गुरबा हैं उनकी भलाई हो सके ।

सभापति महोदय , शौचालय की बात हो रही थी । गांवों में जो गरीब रहते हैं उनकी स्वयं की आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं होती कि शौचालय का निर्माण करा सके । ऐसी स्थिति में ही सरकार ने जो योजना बनायी है वह योजना शतप्रतिशत सफल योजना कही जा सकती है । उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है । केन्द्र से जो सहायता राशि मिलती है और अपने सीमित कोष से संपूर्ण प्रदेश में ... करने की कोशिश की है ।

सभापति महोदय, मध्य विद्यालय की चर्चा हुई । ... मेरे मध्य विद्यालय ... और प्राथमिक विद्यालय मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जहां चापाकल नहीं है ।

क्रमशः

टर्न–32/राजेश/10•7•2002

श्री जगदीश नारायण चौधरी (क्रमश:):– सभापति महोदय, अधिकांश मध्य विधालयों में शौचालय बन गया है, इसलिए हमारे माननीय विरोधी दल के साथियों का यह कहना कि मध्य विधालयों में शौचालय नहीं बना है, यह इनकी मानसिकता को दर्शाता है, जब तक ये लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, विपक्ष भी सरकार का ही एक अंग होता है, इसलिए सरकार के द्वारा किये गये अच्छे कार्यों के संबंध में जब तक ये लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक यह बिहार राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है । हमने अपने कल और परसों के भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि आरोप लगा देने से बिहार का विकास नहीं हो सकता है, आप सरकार के अच्छे कार्यों को सराहना भी कीजिये, आपलोग केवल निंदा प्रस्ताव ही पेश करेंगे यह उचित नहीं प्रतीत होता है । इसलिए सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से अपने विरोधी साथियों से फिर आग्रह करूँगा कि आपलोग स्वच्छ मानसिकता से कार्य करें, अधिकारियों के अच्छे कार्यों को सराहना करें, सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करें, तभी यह बिहार राज्य आगे बढ़ सकता है और हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है । सभापति महोदय, यह सवाल सारे लोगों के लिए आज महत्व का विषय है, इन्हीं शब्दों के साथ, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री मो०ओबेदुल्लाह:– सभापति महोदय, सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में जो बजट प्रस्तुत किया गया है और उसपर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो बजट प्रस्ताव आज आया है, उसमें [illegible] यानि वित्तीय वर्ष 2001–02 में दो अरब, 6 करोड़, 78 लाख का बजट था जो अभी 2002–03 में बढ़कर दो अरब, साठ करोड़, छियासी लाख, बहत्तर हजार रुपये का बजट आया है और इसमें योजना मद में एक अरब, 22 करोड़, 15 लाख रुपये है और गैर योजना मद में एक अरब, 38 करोड़, 71 लाख 72 हजार रुपये है, यानि की सरकार की यह मानसिकता को दर्शाता है कि योजना मद में एक अरब, 22 करोड़ रुपये के आस–पास है, जबकि गैर योजना मद में एक अरब, 38 करोड़ के आस–पास है, जो कि योजना मद से गैर योजना मद की राशि ज्यादा है । सभापति महोदय, यह ऐसा लगता है कि सरकार गैर योजना मद में ज्यादा खर्च करने की इच्छा रखती है और जो पैसा गरीबों के बीच में जाना चाहिए, वह पैसा सरकार मंशा नहीं रखती है, इसलिए यह सरकार ने योजना मद में कम पैसा रखा है । सभापति महोदय, जहाँ तक सरकार की मंशा है, सरकार ने ग्रामों में शौचालय, पेयजल

को व्यवस्था का, जहाँ तक सवाल है, ढ़ाई वर्षों से, जब से मैं इस सदन का सदस्य हूँ, इन ढ़ाई वर्षों से, मैं देख रहा हूँ कि एक भी नये चापाकल का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि गत सत्र में यह आश्वासन सरकार के द्वारा इसी सदन में दिया गया था कि हम प्रत्येक विधायक के क्षेत्र के, एक-एक पंचायत में, हम 5-5 चापाकल देंगे, लेकिन यह सरकार नकारा साबित हुई, यह सरकार अपनी बात से वापस हो गयी। सभापति महोदय, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस विभाग को पैसा ही उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से एक भी चापाकल, किसी भी पंचायत में नहीं लग सका ।

क्रमशः :

/

र्न-33:10.7.02:सच्चिदा । ॥ व्यवधान॥

भापति ॥ श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव॥: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे कोई माननीय सदस्यगण बोलते हैं तो आप उधर मत बोलिये, इधर देखकर बोलिये ।

श्री मो० ओबैदुल्लाह॥क्रमशः॥: भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी देने का लक्ष्य रखा था । लेकिन इन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है । यह सरासर गलत है, झूठ है । सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है । यह सरकार गरीबों को चापाकल नहीं दे सकी है । यह सरकार अपने आप को "भाई" की सरकार कहती है, सामाजिक न्याय की सरकार कहती है लेकिन आज मुस्लिम मुहल्ले की जो हालत है, उसको बयां नहीं किया जा सकता है । मुस्लिम मुहल्ले की हालत यह है कि पैखाने में पानी है या पानी में पैखाना है । देहातों से बहुत बच्चे पटना में पढ़ने आते हैं और जौनडीस रोग का शिकार होकर वापस अपने घर चले जाते हैं । सरकार की यह स्थिति है । यह सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, इम्पोर्टशीबी सरकार है । यह सरकार सिर्फ कहने के लिए मुस्लिम पक्षधर सरकार है लेकिन इनका कार्यकलाप मुस्लिम विरोधी है । महोदय, आप पटना के किसी मुस्लिम मुहल्ले को देखकर यह जानकारी ले सकते हैं ।

श्री राम चन्द्र पूर्वे ॥मंत्री॥: सरकार पर यह आरोप मत लगाइये । मुस्लिम पक्षधर और सामाजिक न्याय की कोई भी सरकार यह नहीं चाहती है ।

श्री मो० ओबैदुल्लाह: लालबाग मुहल्ला, जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, के बारे में सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार वहां जाकर देखे तब पता चलेगा कि यह सरकार मुस्लिम के साथ कैसा रवैया करती है ।

॥ व्यवधान॥

जहां तक स्वच्छ पानी का सवाल है, सरकार द्वारा स्वच्छ पानी देने की बात तो दूर रही, सरकार खुद डिस्टीलरी का पानी पीकर गरीबों को चापाकल का पानी मुहैया नहीं कराती है । ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है । देहातों में हमारे माँ-बहनें सड़क के किनारे शौचालय करती हैं । जब कोई उस सड़क से पास करता है, तो उनको दिक्कत होती है । इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 55 वर्ष के बाद भी मुहल्ले में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकी है । ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

टर्न- 33/10.7.02/सिन्हा ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): माननीय राज्य मंत्री जी, मंत्रि परिषद के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य को धैर्य से सुनें। सदन की परंपरा रही है शानदार और जानदार आरोप और शानदार और जानदार उत्तर । यह सदन की परंपरा रही है । वक्तव्य में हर माननीय सदस्य कहते हैं, आप उसका उत्तर देंगे । माननीय राज्य मंत्री, आप बैठिये । संसदीय आचरण मंत्रि परिषद के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए । बैठे-बैठे सदन में नहीं बोला जाता है । यह संसदीय आचरण के विरूद्ध है । आप सदन में संसदीय आचरण प्रस्तुत करें ।

माननीय संसदीय मंत्री, आप अपने मंत्रि परिषद के सदस्यों को नियंत्रित कीजिये ।

श्री मो0 ओबेदुल्लाह: सभापति महोदय, जब इस सरकार के समक्ष सच्चाई रखी जाती है तो इस सरकार को बेचैनी होती है । जब आप अपने को अल्पसंख्यक की रक्षा की सरकार कहते हैं तो आपको उसी तरह का आचरण भी करना होगा ।

(क्रमशः)

प्रो० ओबैदुल्लाह(आगरा):- महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब यह सरकार आम जनता को पेयजल मुहैया नहीं करा सकती है जो देहात के और जो ग्रामीण हैं, उनका क्या हाल होता होगा? महोदय, शहरों में जो लो०स्वा० अभियंत्रण के जो नलकूप हैं, जहाँ विधायकगण रहते हैं, वहाँ पेयजल आपूर्ति का पाइप फटा रहने के कारण नाले एवं बरसात का गंदा पानी उसमें प्रवेश कर जाता है जिससे पेयजल के साथ गंदा पानी मिलकर जाता है और माननीय विधायकों को भी गंदा पानी पीने को विवश होना पड़ता है। इस प्रकार जब यह सरकार विधायकगण को शुद्ध पानी नहीं दे सकती है तो इस सरकार से क्या उम्मीद रखा जाये। जब शहरों की यह हालत है तो देहातों की क्या हालत होती होगी, देहातों में रहनेवाले गरीब जनता को कहाँ तक शुद्ध पानी दे पायेंगे। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, यह सरकार गरीबों को शुद्ध पानी नहीं पिला सकती है और यह सरकार [illegible] तीन तिगाड़ी की सरकार है।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कल्याणपुर और [illegible] की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहाँ कई सालों से कभी पानी आता है तो कभी रूठ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रखंड के लोगों को यह सरकार पेयजल नहीं मुहैया करा सकती है क्योंकि वहाँ का जलापूर्ति को ठीक चलना चाहिए, जब से यह चालू हुआ है, पूरी अवधि में एक दिन भी पानी नहीं दे पाई है। महोदय, यह सरकार गैर-योजना मद में ज्यादा अभिरुचि रखती है। क्योंकि यह सरकार लूटनेवाली सरकार है जैसे एक कुर्ते के कपड़े की कीमत 30 रुपया है तो उसकी सिलाई 120 रुपया है। इसी तरह यह सरकार योजना मद और गैर-योजना मदों फासला रखी हुई हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि मोनाजिर हसन साहब पर विशेष ख्याल रखा जावे क्योंकि इनके क्षेत्र के लोगों को भी नहीं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। माननीय मोनाजीर हसन साहब ईसमरा कर रहे हैं। इसलिए सरकार उनके क्षेत्र पर विशेष ख्याल रखेगी, ऐसी मुझे आशा है। जहाँ तक इस विभाग के मंत्री का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि माननीय मंत्री को पूर्ण अधिकार से वंचित रखा गया है। इसलिए उन्हें पूर्ण अधिकार दिया जाये। तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर यह गरीबों एवं [illegible] कमजोर लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, नगरीय विकास विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 79,52,04,000 रूपये का बजट लाया गया है जिसमें गैर योजना मद में 43 करोड़ 54 लाख 4 हजार है और योजना मद में 35 करोड़ 98 लाख रूपया दिया गया है। यह मैं बताना चाहता हूं कि योजना मद में इस सरकार की उत्सुकता है। इसी तरह खनन एवं भूतत्व विभाग के संबंध में वर्ष 2002-03 के लिए 5,43,89,000 रूपये का बजट लाया गया है जिसमें योजना मद में 34 लाख और गैर योजना मद में 5 करोड़ 9 लाख रूपये दिये गये है। सरकार योजना मद में कम और गैर योजना मद में ज्यादा रूचि रखती है।

टर्न-35/मधुप/10.7.2002

श्री मो0 ओबेदुल्लाह : - क्रमशः - तीनों विभाग के प्रतिवेदन से यह लगता है कि सरकार लूट-खसोट में विश्वास करती है, गैर योजना मद में ज्यादा खर्च है ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव) : गैर योजना मद लूट का मद नहीं है, यह समझदारी ठीक नहीं है । इसको दूसरे ढंग से भी बोला जा सकता था ।

श्री मो0 ओबेदुल्लाह : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार के द्वारा हाउस में जो वायदे किये जाते हैं उनको सरकार पूरा करे । सरकार जनता के प्रति कितना सजग है, यह तो बिहार की जनता जानती है लेकिन कम से कम विधायकों के प्रति यह सरकार सजग हो ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 ओबेदुल्लाह : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से चाहता हूँ कि मुसलमानों के प्रति यह सरकार बहुत हमदर्द है तो मुसलमानों को स्वच्छ जल पिलाने की व्यवस्था सरकार करे और उनको गंदगी से निजात दिलाया जाय । खासकर मैं मुसलमान विधायकों और मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि अपने इलाके के जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो गंदगी में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को गंदगी से निजात दिलाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री रामदेव यादव : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो माँग प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, कई एक कार्यक्रम जो जनहित के कार्यक्रम हैं, चाहे वह केन्द्रीय प्रायोजित योजना हो या राज्य प्रायोजित योजना हो, निश्चित रूपसे कई-एक कार्यक्रम ऐसे हैं जिसे सही मायने में यदि धरती पर उतारा जाय तोजो हमारी समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या, उसको हम दूर सकते हैं ।

महोदय, जल ही जीवन है । सही मायने में जबतक हमलोगों को

स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तबतक हमारा जीवन यापन, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता है। यह जो पायलट प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में 625 रुपये में शौचालय बनाने का जो कार्यक्रम है जिसमें 375 रुपये केन्द्र सरकार की ओर से, 125 रुपये राज्य सरकार की ओर से और शेष 125 रुपये जो लाभुक हैं, उनकी ओर से दिया जायेगा। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो आज 80-85 फीसदी गाँव में गरीबी-रेखा के नीचे बसने वाले लोग हैं और इनकी जो माली हालत है, इनपर आज हम यहाँ सदन में विचार करने के लिए बैठे हैं और इस योजना के तहत अभी 15 जिलों को चुना गया है, वे जिले हैं - पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, कटिहार, बेगुसराय, बाँका, नवादा, जमुई, गया, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, इन 15 जिलों को पायलट प्रोग्राम में चयनित किया गया है और कुछ जिलों में इसका कार्यक्रम चल रहा है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सही मायने में यदि इसको प्रचारित किया जाय, लोगों में स्वच्छ रहने की आदत डाली जाय, उनमें यदि जागृति पैदा की जाय, जो गरीब गाँवों में बसते हैं, गंदी बस्तियों में बसते हैं, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, सड़कों पर शौच के लिये जाते हैं, हमारे माँ-बहनें सड़कों पर अपनी लाज बचाते हुये शौच के लिये जाती हैं, उनके लिये यह कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।

(क्रमश:)-

टर्न:36:अंजनी:दि0 10.7.02

...क्रमशः...

श्री• रामदेव यादव : उनके लिए यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण काम है और इस संबंध में मोतीहारी, पटना एवं कई जिलों के यहाँ से राशि आवंटित की गई है और बाँका जो इस पराजित जिला है, उसको कठिनाई हो रही है, राज्य सरकार की ओर से जो राशि जाना चाहिए था वह नहीं जा पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम में सही मायने में, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो सरकार की स्थिति है, इन सभी मुद्दों को यदि हम देखते हैं तो निश्चितरूप से यदि 625 रूपये में जनता जागरूक हो जाय, हमारे पदाधिकारी इसको अच्छी तरह से प्रचारित-प्रसारित करें और हम जन-प्रतिनिधि मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को लें तो जो गाँव की माली हालत है उसमें सुधार आ सकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार इसी सदन में यह चर्चा हुई थी और आज पंचायत के चुनाव हो गये, जो चापाकल का मरम्मति कराना है, इसका अधिकार पंचायतों को दे रहे हैं, मैं उसके पक्ष में हूँ, अधिकार उनको मिलनी चाहिए ताकि विकास की गति तेज हो सके। आज बड़े पैमाने पर जितने चापाकल पूरे बिहार में गाड़े हैं यदि उनका सही ढंग से मरम्मति करा देते हैं तो अधिकांश समस्या हमारी दूर हो जायेगी।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पिछली बार इस सरकार ने जो बन्द पड़े चापाकल थे उसको पूर्णतः नया कर दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। यह बहुत-ही सराहनीय काम है। इसीप्रकार से जो चापाकल वर्षों से गाड़े गये हैं, जो लेप्स कर गया है, ऐसे चापाकल की मरम्मति अच्छी ढंग से करा देते हैं या पूर्णतः नया कर देते हैं तो उससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इस सदन में बैठे हैं, महीनों भर यह सदन चलेगा, अभी जो हालत है एम०एल०ए० फ्लैट एवं अन्य जगहों को, जहाँ माननीय सदस्य रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, बिजली हमेशा गुल रहती है, पानी का घोर अभाव रहता है। छज्जू बाग के इलाके में घंटों-घंटों

बिजली नहीं रहती है। मैं आज आ रहा था, तब भी मैंने देखा कि विधान-सभा का सत्र जब हुआ तो तीन घंटे पहले से बिजली चली गयी, माननीय सदस्य के आवास में कोई चापाकल नहीं है, जिसके कारण दिक्कत होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों के आवास में या आवास के आस-पास एक-एक चापाकल निश्चित रूप से दिया जाय,

...क्रमशः...

श्री रामदेव यादव : [क्रमश:] जिससे हमें शुद्ध पेयजल भी मिलेगा और हमें विधायी कार्य करने में भी सुविधा होगी । सभापति महोदय, पिछले वर्ष इसी सदन में विधायकों की अनुशंसा पर जो 5-5 चापाकल प्रत्येक पंचायतों में विधान-सभा के अन्तर्गत देने का सरकार का जो आश्वासन था, इसके संबंध में कहना चाहूंगा कि वह निश्चित रूप से 5-5 चापाकल प्रत्येक पंचायतों में विधायकों के अनुशंसा पर मिलनी चाहिए महोदय, चूंकि हमलोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमारे पास चापाकल के लिए आती है, वे लोग मुखिया जी के यहां नहीं जाते हैं, वे कहते हैं कि हम जानते नहीं है कि किसका क्या अधिकार है? विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जनता विधायक जी के यहां आते हैं आवास में या कार्यालय में और कहते हैं कि आप चाहेंगे तो हो जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायकों की अनुशंसा पर जो 5-5 चापाकल देने का है, वह निश्चित रूप से मुहैया कराया जाए तभी हम अच्छे ढंग से विधायी कार्य कर पायेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

....

श्री रामाशीष यादव : माननीय सभापति महोदय, आज जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव माननीय श्री भोला बाबू द्वारा रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज जिस विषय पर बात हो रही है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बड़ा ही मूल्यवान विषय है " जल ही जीवन है" यह सब जगह लिखा रहता है । हम जब स्टेशन पर जाते हैं या किसी भी जगह में जाते हैं, लिखा रहता है:- " जल ही जीवन है " और यह सही है कि "जल ही जीवन है । " सभापति महोदय, आजादी के 54 वर्षों के बाद भी बड़े दु:ख के

साथ कहना पड़ता है कि जल और हवा पर सबों का अधिकार था लेकिन उस अधिकार को आज छिन लिया गया है । आज बड़े लोगों के पास पीने के लिए मिनरल वाटर है, पानी को रिफाइन करने के लिए कौन-कौन मशीन लगाया जा रहा है लेकिन गरीबों के पास पीने के लिए जो जल मिलता है, वह फूटा हुआ चापाकल से मिलता है, जो माननीय मंत्री महोदया ने दी है । चापाकल का फिल्टर भी फूटा रहता है, जिसके चलते चापाकल से पानी में बालू निकलता है, कीचड़ निकलता है और गरीब वही पानी पीने के लिए विवश होते हैं । बड़े-बड़े लोगों के घर में शुद्ध पेयजल पीने का पानी रहता है लेकिन वे गरीबों को अपने घर में घुसने नहीं देते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है । हमलोग समझते थे कि माननीय मंत्री काफी सक्षम मंत्री है और उन पर हमलोगों का विश्वास था बहुत ज्यादा विश्वास था । माननीया मंत्री महोदया जिस वक्त घोषणा किये थे कि 5-5 चापाकल सभी विधायकों को उनके अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायतों को दूंगा, उस समय काफी विश्वास हुआ था लेकिन न जाने किस कारणों से यह नहीं दिया गया । इनके द्वारा न तो वाशर, नट, बोल्ट ही गांवों में पहुंचा पाये हैं । माननीया मंत्री महोदया, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप महिला मंत्री हैं और माननीया मुख्य मंत्री भी महिला हैं लेकिन आज किन कारणों से घोषणा किये हुए भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं । हमारे माननीय सदस्य श्री औबेदुल्ला, श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल, श्री जगदीश ना0चौधरी जी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने डा0 लोहिया एवं कर्पूरी जी की भी चर्चा की है, हमलोग चौधरी चरण सिंह जी के मुंह से भी बात सुने हुए हैं, सदन में तो कई नेता यहां बैठे हुए हैं । स्व0 चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि बड़े लोगों के लिए सुलभ शौचालय की

व्यवस्था एक जगह कर दी गई लेकिन हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वे निज रूप में शौचालय जाती हैं, कुछ मनचले लड़के, वाहन मोटर साईकिल से उनके पास से जब गुजरता है, तब वे उस अवस्था में भी उठने के लिए विवश हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सामाजिक न्याय की सरकार है और वे सामाजिक न्याय पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यह गरीबों की सरकार है और यह सरकार किन गरीबों के घर में चापाकल लगाते हैं, चापाकल इतने खराब हैं....

(क्रमशः)

टर्न-38/10-7-2002/मुस्ताक

श्री रामाशीष यादव (क्रमागत): चांपाकल जितना बेनीपट्टी और मधवापुर प्रखंडों में दिया गया उसका सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 900 चांपाकल खराब हैं। अगर पांच चापाकलों की मरम्मति के लिए बिहार सरकार पैसा दे देती तो मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझता। मैं विवश हूं और आज सभी बीमारियों की एक ही दवा है "ऐच्छिक कोष", इधर घोषणा होती है कि हम सामान दे रहे हैं और हम विवश हो जाते हैं "ऐच्छिक कोष" देने के लिए। आज चाहे दवा की आवश्यकता अस्पतालों में तो वहां भी ऐच्छिक कोष का ही सहारा लेना पड़ता है। अभी चूंकि हम जल पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसी पर केन्द्रित हैं। सभापति महोदय, मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि यहां पर एक प्रस्ताव आना चाहिए उन महिलाओं के लिए गरीबों के लिए, उन टोलों में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए, उसकी सफाई के रूप में किसी एक चपरासी या दूसरे किसी व्यक्ति को रखा जाए जिसके द्वारा उसकी देख-रेख हो। नगरपालिकाओं में और दिल्ली जैसी जगहों में इस तरह की व्यवस्था है। यह मेरा सुझाव है और इसी सुझाव के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि नट बोल्ट की भी व्यवस्था सरकार करे और पांच पांच चापाकल देने की जो घोषणा की गयी थी उसे अमली जामा पहनायी जाए।

सभापति महोदय अभी जो आई एम थ्री चांपाकल दिया गया है, वह ऐसा है कि उसमें हाथी को बांधा जा सकता है वह हाथी के बांधने के ही लायक है, उससे पानी नहीं निकलेगा। गांव में लोग उसे हाथी चांपाकल कहते हैं। वह जहां जहां गांव में लगाया गया है देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन पानी नहीं देता है। गांव के लोग इसे लेना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से लोगों को यह कहकर देना पड़ता है कि सरकार ने भेजा है, इसे गाड़ने दीजिए जब दूसरा आयेगा तो आपको फिर देंगे, तब लोग गाड़ने देते हैं। इसी प्रकार तारा [illegible] मार्क की इनी यही हालत है। इसके बनाने के लिए मिस्त्री नहीं मिलते हैं, इसके लिए मिस्त्री को

पहले ट्रेनिंग दिया जा । यह पहाड़ी क्षेत्र के लिए है और उसे समतल में उत्तर बिहार में लगाया जा रहा है जो वहां के लिए उपयुक्त नहीं है । इसलिए सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा चांपाकल हमलोगों के यहां नहीं भेजा जाए ,मधुबनी जिला में नहीं भेजा जाए । इसपर ध्यान दिया जाए और वहां सुलभ चीज भेजा जाए ।

क्रमश:

श्री रामजीव यादव: क्रमश:... सभापति महोदय, अभी नगर विकास विभाग पर की चर्चा का विषय है। नगर विकास मंत्री ने कहा था कि जिस चापाकल में पानी नहीं आएगा उसको उखाड़ कर नया पाइप लगाकर चापाकल देंगे। हमलोगों को विश्वास हो गया कि शहरों में कैसे चापाकलों को उखाड़ कर नया पाइप लगाया जाएगा। हमलोग एच्छिक कोष का पैसा सड़क निर्माण आदि के लिए देते हैं लेकिन उसी रोड पर फटा जलापूर्ति का पाइप का पानी लग जाता है। जहां एक बार सड़क पानी से खराब होती है वहां बार बार पानी से सड़क खराब होती है। माननीय नगर विकास मंत्री ने कैसे चापाकलों को ... उखाड़ने की घोषणा की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, उत्तर बिहार का दरभंगा शहर है वहां पर दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल है, लोग इलाज कराने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहां पर आइ0जी0 स्तर के पदाधिकारी बैठते हैं लेकिन वहां की सड़कों की स्थिति नारकीय है। ... सड़कों पर पानी रहता है सड़क पानी से जलमग्न रहता है। ... अच्छी सड़क नहीं ... पानी। उस दिशा में नगर विकास मंत्री से हमलोग उम्मीद किये थे कि कार्रवाई करेंगे कुछ नहीं हुआ है। माननीय नगर विकास मंत्री पुराने समाजवादी हैं। पहले जब लोक दल में थे तो ऊंची ध्वनी से अपनी बातों को रखते थे पता नहीं वह ध्वनी कहां गयी।

सभापति महोदय, मैं मैनाटांड़ी के बारे में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया और आज भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हम नेपाल के बोर्डर पर हैं। ... मैनाटांड़ी अनुमंडल है 20 हजार की जनसंख्या है हमने निवेदन किया था कि मैनाटांड़ी ... को नगरपालिका में लेना चाहिए जिससे आधार से ... मैनाटांड़ी अनुमंडल का विकास होता। उसी तरह से जलापूर्ति योजना ... से उसका जो नाला है उसका सारा पाइप सड़ा हुआ है ... तरह से चापाकलों की हालत गरीबों के टोलों की है उसी तरह से नाला का पाइप सड़ा हुआ है, लिकेज है, उसका पानी बहता रहता है और लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है। उसकी मरम्मति आवश्यक है। मरम्मति की चर्चा इनके प्रतिवेदन में आया है। जो नगर विकास विभाग की मांग है जिस पर सदन को स्वीकृति देनी है हम नहीं भी देंगे तो सत्ता पक्ष के लोग दे देंगे। मैं इन सारी बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि हम बिहार में हैं और

टर्न-39/ विजय 10.7.02

पूरा बिहार आज हमलोगों के सामने चुनौती का बिहार बना हुआ है। उस चुनौती को हमको कैसे स्वीकार करना चाहिए इस पर सोचना है। जल निकासी भी एक चुनौती है। क्योंकि यदि जल के कारण गरीबों के लड़के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पीलिया बीमारी और कई तरह की बीमारी से ग्रसित होकर इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं बिहारी आया है। महोदय, हर क्षेत्र में बिहारियों का उपहास किया जाता है। उसमें योगदान जल का भी है। बिहार वासियों को शुद्ध जल मिले इसके लिए आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कोशी अमृत पेयजल योजना है। इसका भारी नाम है जिसमें नयी नयी मशीनें नया नया टेक्नोलोजी से लाया गया है। कोशी अमृत योजना के अंतर्गत जो मशीने हैं वे भगवान भरोसे हैं। पता नहीं आकाश से कोई वैज्ञानिक आयेगा तो उसको ठीक करेगा। वहां के जो इसके इंजीनियर हैं टेक्नोक्रेट्स हैं वे इसके प्रति लापरवाह हैं। न उनकी बात को कोई चपरासी सुनता है न कार्यपालक अभियंता और न जे0ई0 सुनता है। कोई सुनने के लिए बिहार में तैयार नहीं है। माननीय श्री रामदेव वर्मा जी बोल रहे थे। मोटर बिजली से चलता है। बिहार में बिजली की क्या हालत है सभी जानते हैं। बिजली नहीं रहने पर पेसू में फोन कीजिए तो कहा जाता है बिजली नहीं है। मिस्त्री से कहा जाता है कि नल ठीक कर दो तो कहता है सामान नहीं है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम तो विरोध पक्ष के हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी वे सारी शिकायतें करते देखा जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इन निरंकुश पदाधिकारियों पर अंकुश लगाये, अंकुश लगाने की जरूरत है, नियंत्रण करने की जरूरत है। महोदय, लोकतंत्र में लोक उपर होता है और तंत्र नीचे लेकिन बिहार में लोक नीचे हैं और तंत्र उपर। क्रमशः

टर्न-40/राजेश/19.7.2002

श्री रामाशीष यादव(क्रमशः):-इसलिए अंकुश लगाने की जरूरत है, मुझे परेशान कर रहा है तो आपको भी तो वह परेशान ही कर रहा है, क्या आपको गंदा पानी नहीं देता है, आप हो या हम, सारे लोगों को आज गंदा पानी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पिलाया जा रहा है । जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमलोग विरोधी दल में है, हमारी बात को पदाधिकारी नहीं सुनता होगा, लेकिन यही शिकायत तो आपलोगों की भी है कि हमारी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद सरकारी पदाधिकारियों द्वारा बात को नहीं सुना जाता है । आपके यहाँ भी शुद्ध पेयजल और शौचालय को साफ कराने के लिए कोई नहीं आता होगा। आपके द्वारा शिकायत करने पर भी सरकारी पदाधिकारी दौड़कर नहीं आता होगा, यानि की आपकी समस्या और हमारी समस्या एक ही जैसी है । इसलिए सभापति महोदय, आपने हमें समय दिया, हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं । जयहिन्द, जय भारत ।

श्री सुलतान अहमद:- माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, "जल ही जीवन है" । जल के बिना कोई भी जीव-जन्तु, जिंदा नहीं रह सकता है तथा पेड़ पौधा भी जिंदा नहीं रह सकता है । महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सर्वेक्षण के हिसाब से, जो आँकड़ा आया है, उसमें है कि 80 प्रतिशत लोग जो बिमार होते हैं, उनको बिमार का कारण, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं मिलने के कारण, वे बिमार होते हैं और इसका अधिकांश असर हमारे बच्चों पर पड़ता है । महोदय, भारत सरकार द्वारा जो मापदंड, पानी की आवश्यकता निर्धारित की गयी है, उसमें है कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, जिसका इंतजाम, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर रहा है । महोदय, शुद्ध पेय जल के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील है । शुद्धपेयजल बिहार वासियों को मिले, इस दिशा में हमारी सरकार जागरूक है, इसकी उपलब्धता के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है और यही कारण है कि वर्ष 2000-01 में हमने, हमारी सरकार ने 6 लाख 84 हजार 597 अदद चापाकल तथा 9 हजार 794 ड्रिलिंग चापाकल का निर्माण कराया है । महोदय, हमारी सरकार शुद्ध पेय जल की उपलब्धता की दिशा में, मात्र यही नहीं महोदय, बंद पड़े चापाकलों के लिए भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि उपलब्ध करायी गयी है और पूर्ण स्वच्छ अभियान के तहत जहाँ पायलट योजना के नाम से, 15 जिलों में कार्य करने के लिए प्रोग्राम बन रहा है जिसमें राज्य सरकार को 70 प्रतिशत की राशि उपलब्ध करानी होगी ।

टर्न-40/राजेश/10.7.2002

महोदय, यही नहीं, मेरी सरकार चौमुखी विकास के लिए दृढ़संकल्प है ।

क्रमशः :

टर्न-41/10.7.02:सच्चिदा ।

श्री सुल्तान अहमद : क्रमशः : महोदय, मेरी सरकार चहुंमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील हैं । नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में योजनायें ली जाती हैं जबकि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, चाहे वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण हो । इसी कारण से लोग देहातों से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और दूसरी तरफ शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है । उनकी सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है । उनको सहुलियतें पहुंचाने के लिए, सैनीटेशन के लिए, नगर निगम या नगर परिषद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं । लेकिन निश्चित रूप से जितनी राशि चाहिए, उतनी राशि की उपलब्धता नहीं है । जो लोग नगर में रहते हैं और जो जन प्रतिनिधि हैं, उनकी रूचि उसमें रहती है तो उनके लिए कार्य प्रगति की ओर बढ़ती है । जन प्रतिनिधि लोग अपने हेड से नाली सफाई, लैट्रीन सफाई के लिए फंड उपलब्ध कराते हैं । निश्चित तौर से मजदूर की कमी रहने के कारण भी मशीन द्वारा सफाई होती है । आम नागरिकों में थोड़ी सिविक सेन्स पैदा करना होगा कि कूड़े को किस जगह फेंके । अगर सारी जवाबदेही नगर ईकाई के माथे थोप दें तो काम नहीं होगा।

राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना के तहत काम हो रहा है । शहरों में स्लम योजना के तहत काम हो रहा है । राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना के लिए जो राशि उपलब्ध करायी जाती है, उसमें स्पष्ट निदेश रहता है कि उस राशि का 10 परसेंट राशि गरीबों, जनजाति के लिए खर्च करना है चूंकि शहर में इन्दिरा आवास का प्रावधान नहीं है । इसलिए उस राशि का 10 परसेंट उनके मकान बनाने, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने और पार्क बनाने पर खर्च किया जाता है । हमारे जिला में गंदी बस्ती योजना की राशि गयी तो उसी निदेश के अनुसार काम हुआ ।

अब मैं आपके माध्यम से नगर विकास विभाग के मंत्री जी का ध्यान दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की ओर ले जाना चाहता हूँ । वहां जिस गति से विकास होनी चाहिए, उसकी गति धीमी है । निश्चित रूप से इसका कारण पदाधिकारियों की कमी है । मेरे यहां भायस-चेअरमैन पद पर एडीशनल प्रभार में हैं, सेक्रेट्री नहीं है और जो सहायक अभियंता हैं, वे दूसरी जगह से भाल्को से प्रतिनियुक्त हैं । वे हमारे यहां हैं लेकिन वे रांची के पदाधिकारी हैं । इसलिए इन पदाधिकारियों की कमी के कारण विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उस ढंग से नहीं हो पा रही है ।

टर्न-41/10.7.02:सिन्हा ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकार द्वारा बड़ी-बड़ी योजनाओं को ली जानी चाहिए । गलियां तो एम.एल.ए. या नगर निगम द्वारा भी बनाया जा सकता है । इसलिए जनहित में बड़ी-बड़ी योजनाओं को लिया जाना चाहिए विशेष तौर पर शहरों की जो घनी आबादी है, जो जल-जमाव के कारण ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए ।

इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकार द्वारा बड़ी-बड़ी योजनाओं को ली जानी चाहिए ताकि जल निकासी का कार्य हो और अन्य विकास का कार्य हो ।

§ क्रमशः §

श्री सुल्तान अहमद अंसारी :- श्रीमान् इसके द्वारा दरभंगा नगर निगम पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। दरभंगा नगर निगम में निश्चित रूप से सफाई मजदूरों की कमी है। जो स्थिति नगरपालिका के समय में थी, लगभग वही स्थिति वही स्ट्रेंथ सफाई मजदूरों की आज भी चली आ रही है। वहां बहाली की कुछ समस्यायें हैं। रोस्टर बाधक है, आरक्षण का मामला है। अगर नियुक्ति नहीं होने के कारण अगर वहां सफाई मजदूरों की कमी है तो निगम विशेष रूप से अपने विशेष मशीन के द्वारा प्रतिदिन कुछ निश्चित इलाकों को निर्धारित कर बड़े-बड़े नालों की सफाई करने का काम करें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहां मेडिकल अफसर नहीं है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जो निर्गत करते हैं, उस पद पर जो एक सहायक काम कर रहा है, बल्कि यह कहा जाये कि वह 299 के वेतनमान पर काम कर रहा है। उसके द्वारा निर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लीगली वैलिड भी नहीं है। अगर उसके द्वारा जो जन्म एवं प्रमाण पत्र जो निर्गत होता है, तो न्यायालय में उसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि दरभंगा नगर निगम में एक स्थाई मेडिकल अफसर की पदस्थापना की जाये। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

———

श्री सत्यदेव सिंह – सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पर डिबेट हो रहा है। इसके मालिक माननीया मंत्री श्रीमती रमा देवी जी हैं। महोदय, जीवन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, दवा-दारू और मनोरंजन की आवश्यकता है। लेकिन बिहार में आकर इस सरकार में प्रकृति प्रदत्त वस्तु पानी पर पर भी पाबंदी लग गई है। सामाजिक न्याय की इस सरकार में लोगों को जल भी नहीं मिल रहा है। यह प्राकृतिक सम्पदा है जिसे यह सरकार गरीबों तक पहुंचाने में विफल रही है। सामाजिक न्याय की सरकार जो न्याय के व्यवहार की बात करती है, क्या माननीया मंत्री जी बता सकती हैं कि कितने दलितों को पानी देने का काम किया है? कितने अल्पसंख्यकों को पानी देने का काम किया है? कितने पिछड़े लोगों को पानी देने का काम किया है? आज 40 प्रतिशत जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। आप भीम राव अम्बेदकर की माला जपते हैं, गांधी के भारत की बात करते हैं। गांधी के सपनों की भारत की बात करते हैं, आपने कलंकित करने का काम किया है। आप कहते हैं कि भारत गांवों का देश है, गांवों में खुशहाली होगी तो भारत खुशहाल होगा। आज क्या हो गया है? आज भारत शहरों का देश हो गया है। शहरों में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था है। स्वच्छ जल की व्यवस्था है। दवा की व्यवस्था है। बिल्डिंग पर बिल्डिंग की व्यवस्था है। हवाईट हाउस की व्यवस्था है। बेनामी बिल्डिंग की व्यवस्था है। बैंकों में धन जमा करने की व्यवस्था है। महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिवेदन को पढ़ा है। यह सत्य से बिल्कुल परे है। (व्यवधान)

-क्रमशः:-

: व्यवधान :

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हमने माँग-पत्र को देखा है कि प्रत्येक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। जल ही जीवन है, जल ही आत्मा है, सबकुछ जल ही है लेकिन जल आप कितने लोगों को पिला रही हैं? मंत्री महोदया, आप बताइये, कितने लोगों को पानी दे रही हैं? कितने बच्चों को हम स्वच्छ जल विद्यालय में पिला रहे हैं। विद्यालयों में जितने कल हेलवाये गये हैं उनमें 40 प्रतिशत मृत हो गया है। 120 फीट पाईप हेलाने की जगह आपके पदाधिकारी 40 फीट पाईप हेलाते हैं और 80 फीट बाजार में जाता है। समझ में नहीं आता है कि उसका माल मंत्रिमंडल को भी जाता है क्या? अगर नहीं जाता है तो आपके द्वारा कौन सी कार्रवाई वैसे पदाधिकारियों पर की गई है, कितने पदाधिकारियों को आपने जेल भेजा है? आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि आपने किसी को जेल भेजा है।

महोदय, जब दलित भाई के बस्ती में जाते हैं, अल्पसंख्यकों की बस्ती में जाते हैं, भाई शकील साहब अल्पसंख्यकों के मंत्री हैं, बड़ी लम्बी-लम्बी भाषण करते हैं, एम0-वाई0 समीकरण जिन्दाबाद की बात करते हैं और जब मदरसा में जाते हैं तो पानी पीने के लिए वहाँ से एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दलितों के बीच जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि विधायक जी, नेता जी, चापाकल तो हेला लेकिन दूसरे ही दिन मर गया है। आपने 50 घरों के बीच चापाकल दिया लेकिन वह मृत हो गया। शर्म आनी चाहिये सामाजिक न्याय की इस सरकार को।

महोदय, मेरी सोच है और मैं उम्मीद करता हूँ, सदन में बैठे हुये लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, वास्तव में यदि लोकतंत्र में थोड़ी-सी भी निष्ठा है तो हमको कबूल करना पड़ेगा कि यह शोसल जस्टिस की सरकार नहीं है, शोसल करप्शन की सरकार है, जिसकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिये, वह कम है।

अगर आप पानी देना चाहते हैं तो क्या आप एक सर्वे कराने का विचार रखती हैं ? 54 वर्ष की आजादी के बाद 40 प्रतिशत लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जा रही है तो कैसा यह लोकतंत्र है, यह कैसा प्रजातंत्र है, कैसी जनता की सरकार है, आप बता दीजिये। समाज के 40 प्रतिशत लोग आज भी कुआँ और तालाब का पानी पी रहे हैं, नदियों का पानी पीते हैं, पानी के लिए 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं, पानी के लिए मार खाते हैं और उस राज्य में लोकतंत्र की जय-जयकार किया जाय ? मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। ऐसे लोकतंत्र को परिभाषित किया जाना चाहिये, इसकी विवेचना होनी चाहिये।

महोदय, जहाँ तक मैंने पायलट प्रोग्राम को पढ़ा है, उसमें देखा कि 625 रुपये में शौचालय बनेगा, वाह रे पी0एच0ई0डी0, वाह रे इनके इंजीनियर, इनके टेकनिक से ये 625 रुपये में शौचालय बना देंगे ? महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूँ कि जितने भी पैसे शौचालय बनाने के लिये दिये गये हैं, क्या आपको रिपोर्ट मिली है कि एक भी शौचालय बना है ? बिल्कुल शौचालय नहीं बना है। पैसा उधर से आया, कुछ इधर गया, कुछ उधर गया और गरीब जिसको शौचालय की जरूरत है उसको क्या मिला ? अगर वास्तव में आपकी नियत साफ है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि गरीबों, दलितों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों का उत्थान हो तो उनको जो आवश्यक सुविधायें हैं, वह मुहैया करायें। मैं गुलाम सरवर साहब से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के हितों के बारे में भी थोड़ा चिन्ता करें, त्याग-पत्र दीजिए और त्यागपत्र वापस कर लीजिये लेकिन मुसलमानों के साथ न्याय कीजिये। आज दलितों की हालत, अल्पसंख्यकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है।

टर्न-43/मधुप/10.7.2002

महोदय, मैं माननीया मंत्री, श्रीमती रमा देवी से कहना चाहता हूं कि आप गरीबों को पीने का पानी देना चाहती हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को पानी देना चाहती हैं, दलितों को पानी देना चाहती हैं तो आप एक सर्वे कराइये कि आजादी के 54 वर्षों के बाद कितने लोगों को पानी की सुविधा दी गई है और कितने लोग इस सुविधा से अभी भी वंचित हैं। जिस देश में, राज्य में पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिले, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिले, रहने के लिए घर नहीं मिले, साँस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिले तो धिक्कार है ऐसे देश पर और ऐसे राज्य पर।

(क्रमशः)

श्री सतदेव प्रसाद सिंह : यह सरकार कैसे अपने को सामाजिक न्याय की सरकार कहती है। सभापति महोदय, जहाँतक नगर विकास की बात है, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, पटना को ही देख लिया जाय, नगर विकास कैसे बैठे हुए हैं। नर्क के ढेर पर पटना है, रोग का खजाना है, पैखाना रोड पर बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं, गली में गंदगी व्याप्त है और गरीब लोग वहाँ पर सोते हैं।

सभापति(श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव): अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य श्री राम स्वार्थ राय।

श्री सतदेव प्रसाद सिंह : गांधी ने जो सपना देखा था उसको साकार कीजिए। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं माननीय मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूँ कि वे अपने जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभावें, अगर वे जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तो यह पाप है, उनको सत्ता से हट जाना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति(श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव): अब आप बैठिए, माननीय सदस्य श्री राम स्वार्थ राय।

श्री सतदेव प्रसाद सिंह : मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम स्वार्थ राय : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कोई भी विभाग का बजट हो, उसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को रखने का काम करते है। सभापति महोदय, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि विपक्षी पार्टी सिर्फ सरकार को कोसने का काम करती है। सरकार ने इतने दिनों में क्या विकास का काम किया, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है और न कहीं जिक्र करना आपलोग उचित समझते हैं। माननीय सदस्यों को चाहिए था कि वे अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने-अपने क्षेत्र की चर्चा करते कि हमारे यहाँ इतने आच्छादित गाँव हैं और इतना बिना आच्छादित गाँव हैं। आजादी के इतने दिनों के बाद, उसमें इस सरकार का 12-13 वर्ष हो गये, जो इस सरकार का शासन-काल रहा, उसके बारे में कहीं आप बतलाने का काम करते कि इस राज्य के 49 हजार गाँवों में कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ पेय जल की सुविधा से गाँव आच्छादित हैं।

टर्न:44:अंजनी:दिन 10.7.02

कहूंगा। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, जनता ने जो आपको दायित्व सौंपा है, उसका निर्वहन करते हुए आपको बोलना चाहिए था। लोकतंत्र में विपक्ष की भागीदारी के बिना प्रशासन में स्वच्छता नहीं लायी जा सकती है।

...क्रमशः...

श्री राम स्वार्थ राय : (क्रमशः) महोदय, ये लोग बात करते हैं कि कूड़ा के ढेर पर पटना

बसा हुआ है । पटना में बसे हुए जिम्मेवार नागरिक हैं....

(व्यवधान)

महोदय, मैं बहुत धैर्य से बात को सुन रहा था । यदि सचमुच में चाहते हैं कि गांवों की आजादी के माने गांवों की स्वच्छता है । पहले दिल और दिमाग, दिल और जबान दोनों को बन्द करना होगा । सदन में माननीय सदस्य श्री भोला बाबू उठकर खड़े हो जाते हैं । महोदय, इस सदन के लिए, इस राज्य के लिए इतनी बड़ी जवाबदेही पद पर आने के बाद माननीय सदस्यों को ऐसी बात बोलनी चाहिए, जिससे भावनात्मक ठेस न पहुँचे ।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ । बिहार के 39 हजार गांवों में से कोई भी ऐसा गांव नहीं है, जो एन.एस.विलेज के नाम से जाना जाता हो, जहां जल स्रोत का अभाव हो । कोई भी माननीय सदस्य अगर अपने क्षेत्र के 5 गांवों का नाम दे दें, वे नहीं दे सकते, यह सरकार की सफलता है । लेकिन जानकारी के अभाव में सदन में राज्य की जनता को गुमराह करेंगे, यह ठीक नहीं है । पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकार इन चीजों पर निश्चित रूप से ध्यान देगी । कार्य दक्षता की बात है

सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है, इसके अन्दर भ्रष्टाचार है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ पारदर्शिता है, जिसके बाबत सदस्यगण राय देते और विपक्ष के सदस्यगण भी राय देते। जो संसाधन है, उस संसाधन का बिहार में बेहतर उपयोग करके उसकी उपलब्धियां प्राप्त की जाय। क्योंकि जो सीमित संसाधन है और असीमित मांग का जो असंतुलन है, उसके संतुलन के लिए बिहार के साधन का उपयोग हो। जहां कहीं भी संसाधन का उपयोग बिहार में नहीं हुआ है, दुरूपयोग हुआ है, आप जिम्मेवारी के साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। वास्तव में हम भी महसूस करते हैं कि सीतामढ़ी में भी मैंने जब इसकी जांच करायी कि क्या गड़बड़ियां हैं, क्या भ्रष्टाचार है, वहां पर कागज पर ही आपूर्त्ति एवं वितरण दिखला दी जाती थी.......

श्री नरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य उदाहरण दीजिए।

श्री रामस्वार्थ राय : सबसे पहले उदाहरण देता हूँ - पटना अंचल के अधीक्षण अभियंता श्री अरूण कुमार सिन्हा जी का, इनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। इनके द्वारा जो आपूर्त्ति की गई, जब ये गोपालगंज और पूर्णिया में पोस्टेड थे, उस वक्त करोड़ों रूपया का घपला किये हैं। महोदय, इंजीनियर इन चीफ के टेकनिकल पदाधिकारी के रूप में इन्होंने जो आपूर्त्ति कराया है, वह जाली फर्म के नाम पर। श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता से मिलकर पूरे पटना का काम इन्हीं से लेते हैं। आखिर मामला क्या है, माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। इस विभाग के श्री नारायण साहेब सचिव हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ इन पदाधिकारियों के विरूद्ध जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट सदन के सामने रख रहा हूँ।

टर्न-8 45/आजाद/10.7.2002

सभापति महोदय, अब मैं बाढ़ ग्रसित क्षेत्र खासकर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से लेकर सहरसा का तीनों अगल-बगल जिलों जो बाढ़ ग्रसित है, इनके अधिकतर चापाकल आज 2 फीट, 3 फीट पानी के नीचे हैं । इसके लिए मरम्मति हेड से तत्काल फंड देकर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में गाड़े गये चापाकल को ऊँचा कराकर शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को मिले ताकि महामारी इस बाढ़ में न फैले, इस ओर माननीय मंत्री ध्यान दें, उनकी ओर से इस पर पहल होनी चाहिए । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में राहत . खाने में सहायता मद से इसके लिए राशि नहीं खर्च कर सकते हैं और न इसके लिए सहायता मद में कोई हेड है, कोई सबहेड है कि जिससे खर्चा किया जाय । इसलिए मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री से मेरा आग्रह है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में विशेष आवंटन देकर या कोई विशेष तरीका से इन चापाकलों को ऊँचा कराकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल दिया जाय, जो आपने वादा किया है ....

(क्रमशः)

टर्न-46/10-7-2002/मुस्ताक

श्री राम स्वारथ राम :- मैं चाहूंगा कि सरकार अपने संसाधनों के आलोक में जो वायदा किया है, उसे पूरा करे । यह सभा सत्य बोलने के लिए है, हमलोग यहां सत्य बोलने के लिए आये हैं और मेरी अपेक्षा होगी कि जो घोषणा की जाए, उसे पूरा किया जाए । ... बीते वर्ष पैसा का आवंटन मिला, बिना खर्च किए हुए सब पैसा कहां चला गया, सरेन्डर कर दिया गया । हमलोगों ने आंतरिक संसाधान समिति में नारायणन साहेब को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बतलाया कि आवंटन तो मिला लेकिन वित्त विभाग ने आवंटन को सरेन्डर करा दिया, इसके लिए चिट्ठी ही दे दिया, पैसा कागज पर आया और कागज पर ही चला गया । इसलिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा मंत्री से कहूंगा कि आप माननीय मुख्य मंत्री महोदया से बात करें, ऐसा उपबंध नहीं करावें । पैसा मिले, पैसा निकले भी नहीं, कागज पर पैसा आवे और कागज पर चल जाए, इस तरह से ... भ्रम फैलता है बिहार के लोगों में । इसलिए मैं चाहूंगा कि रियालिस्टिक एप्रोच हो और रियालिस्टिक बजट बने । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव :- सभापति महोदय, मैं सरकार का जो बजट आया है जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग, खनन विभाग एवं नगर विकास विभाग का उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया है लोगों की सरकार पर, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार 1990 के बाद से अब तक . जितना चांपाकल गड़ा है, हर गांव, हर टोले और हर मोहल्ला में, चाहे दलितों का मोहल्ला हो, चाहे पिछड़ों का मोहल्ला हो सभी जगह चांपाकल गड़ा है । महोदय, जो शौचालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग से बनता है, वह हमलोगों के जिला में जितना बनना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले और हर टोले में बना है लेकिन महोदय,

जो गांव में गरीब लोग रहते हैं ,उन्हें यह मालूम नहीं है कि लैटरीन करके पानी डालना चाहिए ,इस कारण से तमाम शौचालय करीब करीब बंद हो गये हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि जो चापाकल ... हमलोगों को ... 5-5 देने का वायदा किया गया था, वह मुहैया नहीं कराया गया ।

क्रमश:

टर्न-47/राजेश/10.7.2002

श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव(क्रमशः):- सभापति महोदय, इस बात के चलते सभी माननीय सदस्य बार-बार इस बात को उठाते हैं तो हमारा भी यह कहना है कि और खासकरके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना है कि जिस बात को सदन में कहा जाय, उसको जरूर लागू किया जाय, क्योंकि हमलोगों के क्षेत्र के लोग भी पेपर पढ़ते हैं और हमलोगजब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे क्षेत्र को जनता द्वारा यह मांग की जाती है कि आपको तो इतना-इतना चापाकल मिला है, लेकिन आप चापाकल नहीं बांट रहे हैं। महोदय, क्षेत्र में तो घूम-घूमकर, टोले-टोले, मुहल्ले-मुहल्ले में लोग, बड़ी तादाद में खड़े हो जाते हैं, फलां जगह पर पैसे के अभाव में चापाकल बंद है, फलां जगह चापाकल नहीं है, इतने वर्षों से वहां पर चापाकल खराब है, उसको चालू किया जाय और उसके बदले में जो नया चापाकल का प्रावधान हुआ है(हमारी सरकार को तरफ से, हमलोगों ने जो अनुशंसा चापा० का किया है, वह सभी जगह चापाकल गड़ा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

महोदय, पिछले सत्र में माननीय मंत्री से मिला था और उनसे मिलकर मैंने आग्रह किया था कि जो तारापंप, जो हाथी छाप चापाकल है, उसका मूल्य 35 हजार रुपया पड़ता है और हमलोगों के इलाके में 7 फीट का पाइप और 10 फीट का जाली लगता है, उस पैसे से यह चापाकल चार-पांच चापाकल हो जायेगा, इसलिए इस चापाकल को ही गड़ाया जाय और जो चापाकल बोरिंग के द्वारा धंसाया जाता है, वह दोबारा गाड़ा भी नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, कहनाचाहता हूं कि जो चापाकल भेजा जा रहा है, हमने मंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि यह चापाकल दिल्ली से आया है, दिल्ली से ही सब लोग सैंक्सन करते हैं, यह चापाकल गड़ने वाला नहीं है, इसलिए दिल्ली की सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाय और जो चापाकल पहले गड़ता था, उसीतरह के चापाकल को गाड़ा जाय और वह चापाकल जिसकी चर्चा मैंने की है, उससे पांच-पांच चापाकल हो भी जायेगा, इसलिए इसपर ही ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत जो चापाकल पुराना था, उसको बनाने के लिए जो पैसा गया है, यह बात सही है कि पहले यह विधायकों की अनुशंसा पर होता था और अब जो पंचायती राज बना है, हमारे जो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार है, उन्होंने बिहार में गरीबों के मुहल्लों में, विकास के लिए पूरा का पूरा पावर, ग्राम पंचायतों को दे दिया है ताकी गांवों का विकास हो। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को, इसको बहुत चिंता है, यद्यपि पंचायत में ही ग्राम सभा कराकर जिस मुहल्ले में चापाकल नहीं है या है, जिसको हमलोग घूम-घूमकर

कर देख नहीं पाते हैं, इतना हमलोगों के लिए यह संभव ही नहीं है कि हम अपने प्रत्येक मुहल्ला-मुहल्ला, टोले-टोले को देख सके, इसलिए अभी जो चुनाव ग्राम पंचायत का हुआ है, यह काम उसी पंचायत समिति को, मुखिया को, जिलापरिषद् को ही यह काम देखना है और पंचायत समिति के द्वारा हर मुहल्ले में चापाकल गाड़ने की कोशिश भी की जा रही है और उनके द्वारा यह गाड़ा भी जा रहा है और इसी कारण से आज गांवों का विकास हुआ है । यह ठीक बात है कि हम उसको अपना फंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिलापरिषद् की बैठक में तो हमलोग जाते ही है, यह बात सही है कि वह हमलोगों से बात भी नहीं करता है, वह इस बात को जानता है कि हम ही लोगों को पूरा पावर है । लेकिन हम महोदय, आपके माध्यम से अपने विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों से कहनाचाहते हैं कि जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, उसकी चर्चा भी आपलोगों को करनी चाहिए लेकिन आपलोग सरकार की उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते हैं, केवल इस सरकार की खामियां ही आपलोगों को नजर आती है, खूबियां नहीं । सभापति महोदय, 1990 से यह सामाजिक न्याय की सरकार है और महोदय, जिस टोला-मुहल्ला में पहले चापाकल नहीं गया था, जिन गरीब गुरुआ के घरों में चापाकल नहीं गया था, इस सरकार से पूर्व केवल जमींदारों के घर में ही चापाकल ले जाया जाता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद, जब से 1990 में सरकार बनी है, आज नगर हो, मुहल्ला हो, गांव हो, चाहे वह दलितों का गांव हो, यह सरकार सभी जगहों में चापाकल गाड़ने का काम किया है ।

क्रमशः

टर्न-48/10.7.02:सच्चिदा ।

श्री विजयेन्द्र प्रसाद सिंह यादव ¤ क्रमशः ¤: महोदय, आरा जिला में नगरपालिका है । वहां अभी जो तत्काल चुनाव हुआ है, वहां हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्त्ता जिलाध्यक्ष बने हैं और वे नगर का विकास करने में सक्षम हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि आरा में 15 तारीख को चुनाव हुआ और 17 तारीख को 17 लाख रूपया नगरपालिका के स्पेशल ऑफिसर ने निकालकर अपने मन से इधर-उधर बांट दिया है । चाहे वह राशि शादी में दी गयी हो या अन्य कार्यों में लेकिन वह राशि बिना नगरपालिका के अध्यक्ष की स्वीकृति के दी गयी, नियम-कानून से काम नहीं किया गया है ।

महोदय, अब मैं खनन एवं भूतत्व विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ । हमारे यहां कोयलवर से बालू निकलता है । पहले से अभी बहुत ज्यादा रूपये पर डाक होता है । हमारे खनन मंत्री माननीय सीताराम बाबू सदन में बैठे हुए हैं । मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बालू निकासी से 8 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया है और उस राशि से जितनी विकास होनी चाहिए, हमारी सरकार भरपूर कोशिश करके विकास कर रही है । मैं ¤माननीय¤ मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चांदी से कोयलवर, संदेश से अजीमाबाद तक बालू निकलता है लेकिन उन जगहों की सड़कें बहुत खराब स्थिति में हैं । इसलिए उन सड़कों की मरम्मति के लिए राशि दी जाय । खनन विभाग की तरफ से रूपया दी जाय ताकि रोड की मरम्मति ठीक से हो सके । पी० डब्लू० डी० का जो रोड बना है, उस पर ज्यादा बालू लोड करके ढोता है जिसके कारण सड़क बहुत ज्यादा खराब हो गयी है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उक्त रोड की मरम्मति के लिए भी राशि उपलब्ध करायी जाय । हमलोगों की सरकार 1990 में बनी है । हमारे मुख्य मंत्री माननीया श्रीमती राबड़ी देवी बनी हैं और उनके शासन-काल में काम भरपूर हो रहा है । आज शहर या देहात में चापाकल मुहैया कराया जा रहा है । यहां एक तरफ महात्मा गांधी के सपोर्टर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ नाथु राम गोडसे का सपोर्टर बैठे हुए हैं । उनका काम विरोध करना है, वे सिर्फ विरोध करते रहेंगे लेकिन हमारा काम विकास का कार्य करना है, हम विकास करते रहेंगे ।

श्री राम कुमार यादव: सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

टर्न-48/10.7.02: सिन्हा ।

महोदय, आज बहुत खुशी की बात है कि विकास हो रही है । हमारे सभी साथियों ने अपना बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूँ कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बारे में जो चर्चा हुई है, वास्तव में यह सही है कि जल ही जीवन है लेकिन जल की स्वच्छता की भी आवश्यकता है । जल की स्वच्छता पर हमारे साथियों ने अपनी-अपनी राय दी है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हिन्दुस्तान है और हमारा जो बिहार है, जो गांवों का राज्य है, उसमें 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं ।

॥ क्रमशः ॥

श्री रामकुमार यादव (झंझारपुर):- महोदय, आज आजादी के 54 वर्षों के बाद भी आज की स्थिति में गांवों में 70 प्रतिशत लोग गंदे जल का पीने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके निदान का रास्ता निकालना चाहिए। जहां तक स्वच्छ जल की बात है, आज दिल्ली, बम्बई, पटना में रहनेवाले लोग स्वच्छ जल पी रहे हैं। गांवों में रहनेवाले लोग गंदे जल पीते हैं। सरकार आंशिक रूप से प्रदान कर रही है। आज गांवों में बड़े पैमाने पर चापाकलों में पी0भी0सी0 पाइप का इस्तेमाल हो रहा है जिसका प्रतिकूल असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है यह ठीक नहीं है। आखिर ऐसे सवाल क्यों खड़े हुए? निश्चित रूप से आजादी के बाद भी सरकार इस पर काबू पा सकी है।

महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य रामदेव वर्मा जी ने भी इस बात को कहा है, गांधी जी के देश में स्वच्छता का कार्यक्रम निश्चित रूप से चलना चाहिए। आज गांवों में शौचालय की भयंकर समस्या है, मां-बहनों के लिए एक गंभीर समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छता एवं शौचालय कार्यक्रम मुस्तैदी के साथ चलाया जाना चाहिए। महोदय, 675 रु0 में शौचालय निर्माण का कार्यक्रम है। इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी है। इस कार्यक्रम को अभी तक लागू करने का काम नहीं किया गया है। एक दो बैठकें हुई हैं। मधुबनी जिला इस कार्यक्रम के तहत है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि लोक स्वा0अभि0 विभाग की जो कन्सल्टेटी कमिटी है, उसका मेंबर हूं, इस कमिटी की बैठक में

इन सवाल को उठाया था, उसमें मिनिस्टर भी थे, मैंने पूछा कि अभी पूरे बिहार के स्तर पर जो हमारे चापाकल खराब है, उनकी मरम्मति क्यों नहीं की जा रही है। जहाँ तक नये चापाकल की बात है, उस बैठक में कहा गया कि सरकार ने फैसला किया है कि 20 करोड़ रूपया जिला परिषद को भेजा जायेगा। जो ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। लेकिन यह 20 करोड़ रूपया सरकार और जिला परिषद के बीच में कहां लटक रहा है, पता नहीं है। आज तक एक भी चापाकल का आवंटन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

मैं मधुबनी जिला के फुलपरास निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। मैं शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा कहना है कि जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, पूरे उत्तरी बिहार में एक भी योजना नहीं चल रही है। अधिकांश योजनाओं में पी०भी०सी० पाईप का प्रावधान किया गया है। जो सही काम नहीं कर रहा है। महोदय, फुलपरास में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 17.5 एच०पी० का मोटर है जिससे पानी निकालने के लिए चार इंच पी०भी०सी० पाईप का प्रावधान किया गया है। यह किस तकनीकी आधार पर हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है।

महोदय, जब 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी फुलपरास से चुनाव लड़े थे, वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय यह योजना स्वीकृत हुई थी और 1973 के बाद से आज तक न तो नाले का निर्माण कराया जा सका है, न लोगों को

जल की आपूर्ति की कमी गई है। यह एक गंभीर मामला है। महोदय, पोखरलीला प्रखंड एक नोटीफाईड एरिया निर्धारित करता है। वहां एक पानी टंकी के लिए शहरी जलापूर्ति योजना के तहत प्राक्कलन बन कर विभाग में प्रस्तावित है लेकिन मात्र 20 हजार रुपये की आवश्यकता है। विभाग ने निर्णय लिया है कि कम्प्यूटीकृत प्लान बनाये जा रहे हैं, विभाग में 6 से 7 महीने से पड़ा हुआ है। बिहार सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है जिसके कारण से वह स्कीम कम्प्यूटीकृत नहीं हो रहा है जिसके कारण स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि 20 हजार रुपया देकर कम्प्यूटीकृत योजना बनाकर इसे जल्दी से चालू करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामसेवक हजारी : सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास विभाग के माँग पर जो कटौती-प्रस्ताव आया है, उस कटौती-प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, अभी-अभी लगन समाप्त हुआ है। गाँव में जब लगन होता है तो बहुत सारी औरतें गाना गाने के लिए आ जाती हैं और जब लगन चला गया तो औरतें अपने कामों में लग जाती हैं। जबतक लगन रहता है तो गाना गाती हैं। महोदय, उसी तरह से हमलोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है जब यहाँ बजट पेश होता है विभिन्न विभागों का तो सभी लोग अपना-अपना गाना गाने लगते हैं। सरकार की भी यही स्थिति है। प्रशासन की भी यही स्थिति है, इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

महोदय, अभी नगर निगम की जो स्थिति है, माननीय मंत्री को साथ में यदि घूमा दिया जाय पटना शहर में तो रात में उनको बुखार हो जायेगा या मलेरिया हो जायेगा या कौलरा भी हो सकता है। जब इनके नाक के नीचे यह स्थिति है तो बिहार राज्य के दूसरे जगहों की क्या स्थिति होगी उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं, जब पटना शहर की ऐसी स्थिति है। महोदय, जहाँ हमलोग निवास करते हैं वहाँ की स्थिति ऐसी है। इतनी गंदगी है, बदबू है, गंदगी का ढ़ेर लगा हुआ है कि रहा नहीं जा सकता है। यह नगर विकास विभाग की हालत है। आज भी पानी उपलब्ध नहीं था तो बाहर से पानी लाकर पीना पड़ा है, नहाने के लिए पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। विगत 2-3 वर्षों से यही स्थिति है। जब आप विधायकों को पानी नहीं दे सकते हैं, उनके आवासों के निकट आप सफाई नहीं कर सकते हैं तो बिहार की आम-जनता को कहाँ तक राहत दिला सकते हैं, उनके लिये क्या कर सकते हैं ? महोदय, आज जो प्रीविलेज लाया गया है, वह प्रीविलेज इस सरकार के विरुद्ध आना चाहिये। पिछले 3 वर्षों से आप

वादा करते हैं कि प्रत्येक विधायकों को 5-5 ट्यूबवेल देंगे अपने-अपने क्षेत्र के लिये लेकिन तीन वर्षों को विधायकों को यह वादा करके जो वादा-खिलाफी कर रहे हैं, वह कहाँ तक उचित है ? यह सरकार स्वयं भी जलील है और सारे माननीय सदस्यों को भी जलील करना चाहती है । अखबारों में निकल जाता है कि प्रत्येक विधायक को 4 ट्यूबवेल, 5 ट्यूबवेल मिलेगा और जब हमलोग क्षेत्र में जाते हैं तो हर जगह लोग पूछते हैं कि सरकार ने तो आपको ट्यूबवेल दिया है, आपने उसको क्या किया ? उनके मन में संदेह हो जाता है कि सरकार ने इनको दिया लेकिन इन्होंने कहाँ गायब कर दिया ? इसलिए हम आपके माध्यम से सभापति महोदय, कहना चाहते हैं कि यदि आपको देना है तो दीजिए, सदन में उसकी घोषणा कीजिये । यदि नहीं देना हो तो सदन में कहिये कि नहीं देंगे । यह आपका भी पैसा नहीं है, केन्द्र सरकार का पैसा है - 377 करोड़ । माननीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ भी बैठक हुई थी लेकिन आपने नहीं दिया । दो वर्षों तक नहीं दिया, यह तीसरा वर्ष है । यदि उसी पैसे से, कुछ जो उसमें अंशदान होता है, मिलाकर दे देते हैं तो प्रत्येक माननीय सदस्यों के नाम पर प्रत्येक पंचायत के हिसाब से 15-15 चापाकल हो जाता है, इसको आप दे दीजियेगा तो यह बहुत बड़ा काम हो जायेगा । और यह केन्द्र सरकार का पैसा है ।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से इतना ही कहेंगे कि जो केन्द्र सरकार का पैसा है, उस पैसे को मिलाकर आपका जो अंशदान है, उसको देकर 3 वर्षों का 15-15 चापाकल प्रत्येक पंचायत के हिसाब से माननीय सदस्यों को देने का काम करें ।

(क्रमशः)-

र्ल:51:अंजनो:दि0 10.7.02

..क्रमशः..

श्री राम सेवक हजारी : तीन वर्षों का 15 - 15 पासबुक माननीय सदस्यों को देने का काम करें।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव) : माननीय हजारी जी, जनता का ही राजस्व है, जनता का ही पैसा है। सरकार उतनी ही घोषणा करे जितना वह लागू कर सके, नहीं तो जन-प्रतिनिधि और जनता के बीच अविश्वास ठीक नहीं होता है।

श्री राम सेवक हजारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से माँग करूँगा कि आप जब सरकारी जवाब दें तो इसमें इस बात को स्पष्ट करें कि माननीय सदस्यों को पासबुक दे रहे हैं या नहीं, यदि नहीं देना है तो इस सदन में आज ही घोषणा कर दें कि पिछले दो वर्षों का किसी भी माननीय सदस्यों को पासबुक नहीं दिया गया और इस बार भी नहीं दिया जायेगा। ताकि माननीय सदस्यों का जो प्रतिष्ठा क्षेत्र में है वह बरकरार रह सके, मैं आपसे आशा करता हूँ कि सरकार अपने जवाब में इस बात की चर्चा करेगा।

श्री राजा राम सिंह : सभापति महोदय,....

श्री गणेश पासवान : सभापति महोदय, मेरे पार्टी से दो माननीय सदस्यों का नाम दिया गया है और मेरा समय 20 मिनट है। माननीय सदस्य श्री राम नरेश यादव बोलेंगे।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव) : सब ही माननीय सदस्य का नाम आता है।

श्री राजा राम सिंह : सभापति महोदय, हमारे नाम पर एम0एल0ए0 फ्लैट 45 और 83 आवंटित है। दोनों मिलाकर तीन बाथरूम है। एक बाथरूम में ऊपर से पैखाना का पानी टपकता चूता है और दूसरे का दरवाजा टूटा हुआ है। किसी में फर्श भी नहीं है और आस-पास में गंदगी है। यह है बिहार विधान-सभा के सदस्य के आवास की स्थिति। महोदय, पूरे विभाग पर क्या कहा जाय, विभाग पर आने के पहले मैं माननीय सदस्य श्री राम सेवक हजारी जी के स्वर-से-स्वर मिलाते हुए कहना चाहूँगा और निश्चित रूप से हमारा माँग है और मेरा आग्रह होगा कि इस बार विधान-सभा में इस सत्र में सदस्यों को पासबुक देने की घोषणा कर दीजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि

र्स:51:अमनो:दि0 10.7.02

इस मिनतों को स्वीकार किया जाए। जितना जलील हम लोगों को किया है आने क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि दूसरे किसी विभाग ने ऐसा जलील नहीं किया। जनता में भ्रम है कि विधायकों को पाँच पाँच लाख मिल गया, और आपने दिया नहीं? इसलिए सबसे पहले मेरी मांग होगी कि आप इस प्रकार घोषणा कर दीजिए। सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का, स्वच्छता का, होमें, मैं जापान गया था तो गाँवों में, वह तो मुझे मालूम था कि वहाँ के गाँव सड़कों से जुड़ी हुई है, बिजली भी गांव में है, इसके अलावे दो अतिरिक्त सुविधायें भी देखा, टेलीफोन का और साथ-ही-साथ गाँव में जलापूर्ति की। हमारा बिहार क्या यह सपना देख सकता है? सपना देख सकता है कि हमारे गाँव में भी जलापूर्ति होगी? कुछ गाँवों में पहले जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी थी, वाटर टंकी बैठाकर किया गया था लेकिन अब तमाम जगह समाप्त हो गये हैं। प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर के कुछ-कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। हम इस संबंध में कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसकी योजना आप बनायें और यह योजना जिलास्तर, अनुमंडलस्तर एवं प्रखंड स्तर के शहरों में अनिवार्य रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था करें। इसके अलावे कुछ औद्योगिक शहर हो सकते हैं, कुछ अन्य बिजनेस सेंटर भी हो सकते हैं वहाँ भी करें लेकिन गाँव में जलापूर्ति व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कीजिए।

....क्रमश:...

श्री राजा राम सिंह : (क्रमशः) एक दूसरा सवाल है कि आज गांवों में नालियां बन रहे हैं और नालियों में गंदगी इतनी रहती है कि गांवों पर मच्छर का स्थायी इन्तजाम हो गया है । मैं तो मुझे याद है कि 10-20 साल पहले गर्मियों के दिनों में मच्छर नहीं हुआ करते थे लेकिन आज के तारीख में गांवों पर मच्छर का इन्तजाम हो गया है और इसके रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, स्वच्छता का उपाय विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है । इसी के साथ यह समस्या इतनी गहरी हो गई है कि पानी जाय तो कहां जाय, नालियों का पानी कहां जाय ? इस सवाल पर प्रत्येक गांवों में विवाद एवं झगड़े होते रहते हैं, निश्चित रूप से यह सरकार का विषय नहीं है, जन जागरण का मामला है । नगर विकास विभाग शहरों के लिए कुछ राशि देती है, जिससे शहरों की हालत कुछ सुधरी है लेकिन इस पर और ध्यान देने की जरूरत है, इसमें और राशि दी जाय और शहरों में नाली की व्यवस्था की जाय ।

सभापति महोदय, मैं माननीयमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप जांच कराकर देख लीजिए, जो चापाकल आपके द्वारा गड़वाया गया है ,उसमें घोषणा के बावजूद 50 प्रतिशत जगहों पर चापाकल के पास प्लेटफार्म नहीं बना सके हैं, ऐसे ही चापाकल लगा हुआ है और पानी , चारोंओर गिरता है और गन्दगी फैला हुआ है । आखिर प्लेटफार्म लगाने का पैसा मिलता है तो वह पैसा पदाधिकारियों xxxxxxx लोग खा जाते हैं। क्योंकि प्लेटफार्म नहीं रहने से वह पानी नीचे जाता है और फिर चापाकल के द्वारा वही गन्दा पानी आता है । इसलिए मैं माननीयमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन जगहों पर प्लेट-फार्म क्यों नहीं बनवाया गया, वह राशि कहां चली गई, इसकी जांच होनी चाहि

(लाल बत्ती)

श्री राजा राम सिंह : सभापति महोदय, लाल बत्ती जल गई है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री राम चरित्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं सरकार के द्वारा उपस्थापित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं खनन भूतत्व विभाग के खिलाफ तथा कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, सरकार ने अपने किताब में एक बड़ा ही लुभावना नारा के .. रूप में प्रदर्शित किया है "जल ही जीवन है और स्वच्छता प्राण है " लेकिन जिस तरीके से किसी भी मनुष्य के चेहरे में देखने से उस मन: स्थिति का अध्ययन किया जाता है । महोदय, जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना के इन तीनों विभागों के माध्यम से जो सारी योजनायें और इन योजनाओं के पीछे किये गये खर्च का मूल्यांकन किया जाय तो पूरे बिहार का सरकार के चेहरे के बारे में जो ... प्रतिबिम्ब है, वह प्रतिबिम्बित होता है । चाहे भू-खनन का सवाल हो, हमारे इस पटना नगर में ......

(क्रमश:)

टर्न-53/10-7-2002/मुस्ताक

• श्री राम चरित्र प्रसाद सिंह (क्रमश:) :- कुम्हरार के पुरातात्विक संस्थान को चलकर देखा जाए, उसकी क्या स्थिति है और खनन विभागकी क्या मानसिकता है ?

श्री सीराम सिंह (मंत्री):- यह खनन विभाग का नहीं है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):- माननीय मंत्री कह रहे हैं और यह सही भी है कि वह खनन विभाग का नहीं है आर्केलोजी विभाग के साथ है।

श्री राम चरित्र प्रसाद सिंह :- नगर विकास विभाग के राजधानी देखकर इसके मन: स्थिति सिद्ध हो जाती है। जैसा कि अभी हमारे विधान सभा में विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा तारांकित प्रश्न और आजके डिबेट से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जब विधायकों के फ्लैट में स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पायी है, विधायकों के साथ क्या सरकार की यह मानसिकता है तो स्पष्ट है कि इसे ही स्वच्छ पानी प्रदान नही कर सकती है तो यह चिंतनीय विषय बन जाता है वह ग्रामीणों के लिए दलितों के लिए जो दिहात और मोलों में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति यह कहां तक अपनी स्वच्छता और जल ही जीवन है का के स्वरूप इन्होंने प्रस्थापित करने की कोशिश की है तो मैं यह कह सकता हूं कि जल ही जीवन है, स्वच्छता प्राण है, ये दोनों की हत्या करने की कोशिश पूरे प्रदेश में इन्होंने की है, इसे नकारा नहीं जा सकता है।

महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान इंगित करना चाहता हूं। विगत वर्षों में 1997-98 और 1998-99 में भारत सरकार से तीन करोड़ रु० का प्रावधान ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बिहार सरकार को किया गया लेकिन, माननीय सदस्यों द्वारा इसी सदन में इस बात को उठाया गया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसी विषय पर बैठक बुलाकर तमाम सदस्यों को चांपाकल प्रति पंचायत जो पड़ने वाले थे, देने का आश्वासन इसी सदन में दिया गया था। आज 2001-2002 और 2002-2003 तक मे किसी भी

माननीय सदस्यों को यह चापाकल प्रदान नहीं किया गया । यह बात जो अखबारों में आयी ,इससे तमाम जन प्रतिनिधियों को जनता का जबर्दस्त दबाव पड़ा और जनता इसे मानने में सक्षम नहीं हो रही है । इससे विधायकों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आज इस सदन में आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा कि विगत तीन वर्षों का जो 15 प्रति पंचायत प्रत्येक विधायक देने के लिए जो इन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था ,उसे आज घोषणा के रूप में इस बात को आश्वस्त करें ताकि हम सभी विधायक जनता को शुद्ध पानी पिलाने के लिए कारगर कदम उठाने में सक्षम हो सकते हैं । साथ ही साथ मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । हमें दस मिनट समय मिलना चाहिए ,कैसे हमारे समय में कटौती की गयी ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):- माननीय सदस्य, आप सात मिनट बोल चुके हैं ,ऐसा नहीं है कि आपके समय में कटोती कर दी गयी है ,आप सात मिनट बोल चुके हैं ।

श्री राम चरित्र प्रसाद सिंह :- मैं अपने विधान-सभा क्षेत्र हिलसा की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं । हिलसा नगर पंचायत है और मंत्री महोदय ने 60 नगर पंचायतों का जिक्र किया है , इस नगर पंचायत में आज तक पीने के पानी व्यवस्था नहीं की गयी है । जो प्रतिवेदन रखा उन सारी वस्तुस्थिति का मूल्यांकन कीजिए कि हिलसा नगर की क्या स्थिति है ? साथ ही साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि थरथरी प्रखंड में जो ग्रामीण जलापूर्ति चलाया गया लेकिन आज बिजली के अभाव में तो कभी आन्तरिक गड़बड़ी की वजह से या पाईप के रिसाव से यह ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठप पड़ा हुआ है ।

क्रमश:

टर्न-54/राजेश/10.7.2002

श्री रामचरित्र प्रसाद सिंह (क्रमशः):- सभापति महोदय, एकंगरसराय ग्रामीण जलापूर्ति ठप्प है, हिलसा ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठप्प है, यह स्थिति है महोदय। महोदय, हिलसा जो आज अनुमंडल है और एकंगर जो प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर जब जलापूर्ति व्यवस्था इनको बंद है तो आप इसका अंदाजा स्वयं कर सकते हैं। सभापति महोदय, आज जलापूर्ति की स्थिति बद से बदत्तर स्थिति में है, हमारे यहाँ की जनता आज स्वच्छ पानी पीने की स्थिति में नहीं है, हमारे क्षेत्र की जनता बद से बदत्तर स्थिति में जीवन जी रही है।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):- अब आप समाप्त करें।

श्री रामचरित्र प्रसाद सिंह:- महोदय, हमारे यहाँ के दलित लोग, आज नदी का पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। महोदय, हमारे यहाँ चापाकल में कहीं भी प्लेटफार्म नहीं बना है, जैसा कि हमारे माननीय दोस्त श्री राजाराम सिंह जी ने कहा कि जो चापाकल गाड़ा भी गया है, वहाँ पर प्लेटफार्म नहीं बनाया गया है, इसका पैसा किसी न किसी अधिकारी के पॉकेट में चला गया है......

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):- अब आप समाप्त करें।

श्री रामचरित्र प्रसाद सिंह:- सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, ... पाइप जो 300फीट गाड़ा जाना चाहिए, वह मात्र 150 फीट ही गाड़ा गया है, जो 100 फीट में पाइप को जाना चाहिए वह मात्र 60 फीट ही पाइप डाला गया है और इसका नतीजा यह है कि जो नीचे स्तर से पानी प्राप्त होना चाहिए था, वह पूरा पाइप नहीं जाने के कारण आज लोग शुद्ध पानी पीने से वंचित है। आज महोदय, इस सरकार के द्वारा आम जनता के साथ बड़ा ही खतरनाक स्थिति पैदा करने की कोशिश की गयी है। सभापति महोदय, आज हिलसा का जो कार्यपालक अभियंता है, उसका ध्यान इस ओर है ही नहीं, मैं जब भी ....

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):- अब आपका समय समाप्त हुआ। माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग।

श्री श्रीनारायण यादव (मंत्री):- माननीय सभापति जी, बहुत सारे माननीय विधायकों ने अपनी बातों को सदन में रखा है, हम तो यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि माननीय सदस्यों का कुछ सुझाव आयेगा। सुझाव तो आया ... नहीं, लेकिन लांछन जरूर लगाया गया। उलटा इनका कर्तव्य बनता है कि यदि सरकार की ओर से केवल कथनी हो, करनी न हो, तो उसको ये लोग उजागर करें। महोदय, आज गावों को छोड़कर लोग शहरों की ओर पलायन करते चले जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर आज गाँव को छोड़कर शहर में जा रहे हैं और यत्र-तत्र वे बसते चले जा रहे हैं और बसने से पूर्व वे कभी इस बात को नहीं सोचते हैं कि कहाँ से सड़क जायेगा

कहाँ से जायेगा नाला, कहाँ पर नाले का निर्माण होगा, सिवरेज लाइन का सैक्सन कहाँ होगा और इसी का नतीजा यह है कि शहर आज गंदी बस्ती में परिणत हो रहा है । महोदय, जरूरत थी कि बसने से पूर्व सोचते कि हम जहाँ बसने जा रहे हैं, जिस चकाचौंध शहर की ओर हम भागते चले जा रहे हैं, हम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि कम से कम सड़क जाने का रास्ता है कि नहीं, वहाँ पर ड्रैनेज जाने की जगह है कि नहीं, वहाँ पर नाली बनाने की जगह है कि नहीं, लेकि लोग बसते चले जा रहे हैं और जब जल जमाव होता है या और कुछ होता है तो ये लोग कहते हैं कि इसके लिए सरकार दोषी है । महोदय, मैं इसलिए इस बात को रखना चाहता हूँ कि किसी भी शहर के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बसनेवाले लोग इस बात का ख्याल जरूर रखें कि उनके घर के आगे कम से कम 20 फीट का रोड हो । महोदय, हम यह नहीं कहते है कि सरकार का दायित्व नहीं बनता है, सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हुआ था, तब तक पूर्ण दायित्व सरकार पर था, लेकिन आज चुनाव हो गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में हमने नगर निकायों का चुनाव कराया ।

क्रमशः

श्री श्रीनारायण यादव (मंत्री) (क्रमश:): नगर पंचायत और नगर परिषद की समिति भी गठित हो गयी, केवल नगर निगम का होनेवाला है । सारे अधिकार नगर पंचायत समिति, नगर परिषद समिति को है और नगर निगम का गठन हो जाय तो वहां का दायित्व भी उन्हीं को बनेगा लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति नगर निकाय की है, वह जर्जर है, उनके पास पैसा नहीं है कि नगरों की सुविधाओं के बारे में अपने स्तर से कार्य कर सकें । उनको सरकार का एसीसटेन्स चाहिए, हमारी मदद चाहिए । मैं कहना चाहता हूँ कि उनका अपना एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में प्रोविजन है होल्डिंग टैक्स का । होल्डिंग टैक्स पुराने जमाने से चला आ रहा है । पुन: उनको कर निर्धारण करना चाहिए था लेकिन असेसमेंट नहीं हुआ है । आप, महोदय, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं । नगर विकास मंत्री की हैसियत से आपने भी अनुभव किया होगा कि जितने निकाय हैं, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि उसको ठीक करना कठिन है और उसका मूल कारण है कि उनको जो अपना श्रोत पैदा करना चाहिए था आमदनी का, वह नहीं है । यह दिक्कत है । कई वर्षों से चुनाव नहीं हुआ था । अब चुनाव हो गया और उनको नये सिरे से कर निर्धारण करना है, प्रोफेसनल टैक्स लगाना होगा और अपना श्रोत पैदा करना पड़ेगा । जबकि उनका पहला दायित्व बनता है नगरों को सुविधा प्रदान करना । हम भी उनकी मदद करेंगे इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं । महोदय, मुझे कहते हुए फख्र होता है कि बिहार में जो नीति बनी है उसकी/प्रशंसा भूरी-भूरी न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर भी हुई । यू० एन० ओ० में उठायी गयी । अगर उसी फार्मूला के आधार पर कर निर्धारण हो तो किसी को शिकवा शिकायत नहीं हो ।

पहले हुजूर होल्डिंग टैक्स लगता था । वह मनमाने ढंग से होता था । जिसको 50 हजार रूपया लगना चाहिए, उसको पांच हजार रूपया लगता था और जिसको पांच सौ रूपया लगना चाहिए था, उसको पांच हजार लगता था । इस पद्धति के अनुसार किसी को कोई शिकायत नहीं होती ।

हमने नगर को 3-4 भागों में बांटा है । शहर की श्रेणी अलग-अलग ए बी सी होगी । जो मुख्य सड़क है, उसका रेट यह होगा, जेनरल रोड का रेट यह होगा और उससे कम रेसीडेन्सियल एरिया का रेट होगा ।

टर्न- 55/10.7.02/सिन्हा ।

जब मैं वर्ष 1993 में नगर विकास विभाग का राज्य मंत्री चुना तो मेरे सामने यह बात आयी । हमने अपने पदाधिकारियों की बैठक में पूछा कि अगर पटना का कर निर्धारण इस पद्धति से हो तो बताइये कि कितना रूपया आयेगा तो पदाधिकारियों ने कहा कि 60 करोड़ रूपया आयेगा । हमने कहा कि हम 40 करोड़ पर ही निर्धारित करते हैं और आपलोग 40 करोड़ रूपया एकत्रित कर दें । असेसमेंट वर्क भी आरंभ कराया । मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि लाख सरकार सतर्क हो जाय लेकिन बईमान लोग उसको चलने नहीं देते हैं । असेसमेंट हो गया और एक महीना के लिए जो प्रेसीडेंट रूल लगा था, उसमें सारे लिफाफे को जला दिया गया । पुनः हमको असेसमेंट वर्क कराना पड़ रहा है ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल सरकार पर लांछना लगाने से कोई बात नहीं बनती है । सरकार आपके सहयोग और आम नागरिक के सहयोग का आकांक्षी है । उसको मदद करनी पड़ेगी ।

§ क्रमशः §

श्री श्री नारा. ा जादव[मंत्री]:- कि पटना नरक बन गया । मैं यह नहीं कहता। कहने को आपको आजादी है। आप कह लीजिये कि पटना नरक बन गया । महोदय मैं प्रतिदिन सफाई करवाता हूं।

[व्यवधान]

पहले मेरी बात को सुन लीजिये । मैं प्रतिदिन सफाई का कार्य करवाता हूं। लेकिन जिनकी जो आदत बन गई है, वहां पर फिर कूड़ा करकट जमा कर रख देते हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक दम दुर्गंध आती है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि सदन के बाद आप मेरे साथ चलिये और अगर आपको नाक पर रूमाल रखने का मौका मिल जाये तो हम मान लें ।

[व्यवधान]

मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे साथ चलिये । मैं आपको आमंत्रित करता हूं।

[व्यवधान]

सभापति [श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव]:- माननीय मंत्री, आपका समय समाप्त हो गया है आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री श्री नारायण यादव[मंत्री]:- माननीय सदस्यों ने कुम्हरार की बात उठायी । कुम्हरार में जल-जमाव की समस्या को समाप्त करने के लिए 51 लाख रूपये की योजना बनाई है जिसके विरूद्ध हमने 10 लाख जमा कर दिया है। इस तरह से जलापूर्ति के संबंध में बातें उठाई गयी । मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं और इस बात को स्वीकार करता हूं।

[व्यवधान]

शुद्ध जल की अपेक्षा करते हैं। शुद्ध जल नहीं दे पा रहा हूं। इसका मूल कारण यह है कि पाईप लाईन काफी पुराना है और जंग लग गया है जिसके कारण वह टूटता रहता है। महोदय, सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो यह आपकी मरजी ।

श्री सीताराम सिंह (मंत्री):- सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की मांग पर मैं हस्तक्षेप करते हुए खनन एवं भूतत्व विभाग के बारे में कुछ जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ।

महोदय, बिहार के बंटवारे के बाद पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं आपको बिहार के खनन एवं भूतत्व के संबंध में सदन को जानकारी दूँ।

(व्यवधान)

महोदय, यह बात सही है कि भारत वर्ष में बिहार खनिज सम्पदा की दृष्टि से सबसे सम्पन्न और समृद्ध राज्य रहा है। बिहार नम्बर एक राज्य है अविभाजित बिहार। भारत वर्ष में जो भी खनिज सम्पदा उपलब्ध थी, उसका लगभग 25 प्रतिशत खनिज सम्पदा बिहार के अंदर थी।

क्रमशः :-

टर्न-57/मधुप/10.7.2002

श्री सीताराम सिंह (मंत्री) : क्रमश: - महोदय, बिहार बँटने के बाद की जो स्थिति है, वह मैं आँकड़े देकर एक-दो मिनट में बताना चाहता हूँ ।

महोदय, अविभाजित बिहार, वर्ष 2000-2001 में जब पूरा बिहार एक था तो 757 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी । महोदय, जब बिहार बँटा तो मात्र 39 करोड़ रुपये बिहार को मिले । वर्ष 2001-02 में वह बढ़कर 41 करोड़ रुपये हुये हैं । महोदय, जब तक जब बिहार एक था, आपको मालूम है, कोयला से सोना तक बिहार के अन्दर था, ताँबा से बॉक्साईट तक बिहार के अन्दर था । जब बिहार विभाजित हुआ तो मात्र दो खनिज पदार्थ आपके पास मुख्य रूपये बचा है - एक तो चूना पत्थर और दूसरा पायराईट । चूना पत्थर जो रोहतास जिला में मिलता है, वह भी सैंक्चुअरी - वन विभाग के अन्दर चला गया है और उसमें अब नया लीज नहीं दिया जा रहा है । महोदय, आज बिहार के अन्दर एक ही सीमेंट फैक्टरी कल्याणपुर चल रहा है और वह भी लड़खड़ा गया है क्योंकि अब नये नियम-कायदे से नया लीज नहीं मिल रहा है । जो भी पहले लीज दिया गया था उसी लीज के आधार पर जो खनन कार्य कर रहे हैं, उससे अधिक का नहीं मिल रहा है । दूसरा, पायराईट है - अमझोर में जो फैक्टरी लगा था जहाँ उर्वरक बनाया जाता था, सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर भेजा जाता था, आज उसकी खपत कम है इसलिए वह फैक्टरी भी बिल्कुल बन्दी के कगार पर है । इस तरह से अब हमलोगों के पास दो ही खनिज पदार्थ बच गये हैं ।

महोदय, हमारे पास जो माईनर मिनरल्स बचे हैं उनके द्वारा हमको बहुत कम राजस्व प्राप्त हो रहा है । यह तो जाहिर है महोदय, कि जिस दिन बिहार बँटा उसी दिन राजस्व घटा । एक वक्त था जब बिहार बँटते समय भारत सरकार से जो पैकेज की माँग की गई थी, भारत

सरकार के द्वारा पैकेज भी नहीं दिया गया । महोदय, अगर खनिज विभाग के द्वारा किये जा रहे वसूली के बराबर भी पैकेज भारत सरकार से मिलता तो प्रति वर्ष बिहार के विकास में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जरूर हो जाती ।

महोदय, आज की स्थिति में जो हम कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उसकी जानकारी हम सदन को देना चाहते हैं । महोदय, जमुई जिले के मंझोस में आयरन और मैगनेटाईट प्राप्त हुये हैं और एक वर्गकिलोमीटर के अन्दर अभी तक जो जाँच हमलोगों ने कराया है, जिओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा और बिहार सरकार की जो एजेन्सी है, उसमें एक्जेक्ट पूरी जानकारी नहीं है लेकिन एक वर्ग किलोमीटर में मैगनेटाईट प्राप्त होने वाला है और उसके डेप्थ से उसका क्वानटिटी क्लीयर होगा ।

महोदय, दूसरी चीज जो हम बिहार के अन्दर अभी करने की पोजीशन में आ गये हैं - वह है ग्रेनाईट । इसमें हमलोगों ने कार्रवाई की है, भारत सरकार ने भी इसमें प्रयास किया है और जिओलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जाँच से गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में ग्रेनाईट की प्राप्ति हुई है । महोदय, इसको बाहर सप्लाई करने के लिए जिस स्लैब में और जिस चौड़ाई और लम्बाई में कि इसको बाहर आपूर्त्ति किया जा सके, वह हमको मिल नहीं रहा है वैसा ब्लौक । इससे बेहतर के साईज की दिशा में प्रयासरत हैं जिसकी जाँच कराकर बेहतर ब्लौक बना सकें ।

महोदय, आज सबसे बड़ी बात जो आपको मालूम है, आप जानते हैं, आपका जोन है, पूर्णियाँ के बेसिन में पेट्रोलियम प्रोडक्टस की बात आई है, उसमें हमलोगों ने जो प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी इसमें प्रयास किया है और उस प्रयास के तहत उसका टेन्डर भी हो चुका है और टेन्डर का रेट निर्धारित है ।

श्री राजा राम सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, कहना यह है कि मंत्री जी ने भी यह बताया कि सीमेंट का निर्माण भी रुकने वाला है, हमारा यह कहना है कि इसके पहले सड़क निर्माण में मिट्टी नहीं मिल रहा है, दूसरी बाधा सीमेंट की सामने आ गई है। हमारा यह कहना है कि आखिर इन्हीं का विभाग है जो बाधा विकास के कार्यों में डाले ?

टर्न:59:अमनी:दि0 10·7·02

श्री सीताराम सिंह(मंत्री): 25 अगस्त को भारत सरकार ने टेंडर का डेट निकाला है पूर्णिया में पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के लिए ।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): कोशी एवं महानन्दा नदी में मिलने की महीने से ऊपर सर्वेक्षण भारत सरकार कर रही थी और 15 अगस्त को होगा···

श्री सीताराम सिंह(मंत्री): महोदय, 25 अगस्त को होगा और उसे प्राप्त होने से बिहार का विकास होगा, बिहार के विकास में बढ़ोत्तरी होगी। महोदय, इसके अलावे बिहार के अन्दर अब ईंट, बालू और पत्थर बचता है। मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि ईंट से भी हमलोग बेहतर परफोरमेंस कर रहे हैं। वर्ष 2000-01 में 10 करोड़ रूपया राजस्व मिल रहा था, 2001-02 में 11करोड़ 70 हजार पर ले गये और इस वर्ष 2002-03 में 16करोड़ 50हजार रूपया लक्ष्य रखा गया है··

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): एक बात माननीय मंत्री, 15 अगस्त जो तिथि टेंडर के लिए रखा गया है या सर्वेक्षण के लिए ।

श्री सीताराम सिंह(मंत्री): महोदय, 25 अगस्त है, यह सर्वेक्षण के लिए है।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): सर्वेक्षण तो हो चुका ।

श्री सीताराम सिंह(मंत्री): उसी का होगा ।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): ड्रीलिंग करने के लिए है।

श्री सीताराम सिंह(मंत्री): जी हाँ । इस तरह से हमलोग इन सब चीजों से भी राजस्व की वृद्धि कर रहे हैं। बालू में जहाँ राज्य सरकार को 18 करोड़ रूपया मिल रहा था, उसमें हमलोग इस वर्ष 2002-03 में 26 करोड़ करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अभी कुर्सी मंडल से कटाव का काम चल रहा है उसका भी हम सेटेलाइट से सर्वेक्षण करा रहे हैं और उसका प्रतिवेदन बना रहे हैं, प्रतिवेदन बनने के बाद सिंचाई विभाग को देंगे ताकि बाढ़ के कटाव से रोकने के लिए, बाढ़ का परमानेंट निदान के लिए आगे से सुविधा होगी और उसका उपाय सोचा जा सकता है।

धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): अब सरकार का जवाब होगा, माननीया मंत्री श्रीमती रमा देवी।

श्रीमती रमा देवी (मंत्री): सभापति महोदय...

(व्यवधान)

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): आपलोग सरकार का जवाब तो सुनिए।

श्रीमती रमा देवी (मंत्री): सभापति महोदय...

(व्यवधान)

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): माननीया मंत्री खड़ी ही हुई और तुरंत घोषणा ही कर देंगी, घोषणा तो अन्त में होता है।

(व्यवधान)

आपलोग बैठिए। सरकार का जवाब सुनिए, आपलोग बीच में रोक देते हैं।

(व्यवधान)

अब कोई सूचना नहीं, समय नहीं है।

(व्यवधान)

जो सूचना है आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें। माननीया मंत्री, आप बोलिए।